

नई दिल्ली
शनिवार
31 अक्टूबर 2026
वर्ष: 13, अंक: 57
पृष्ठ: 08, मूल्य 2 रु०

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhawnatoday@gmail.com

web: www.sadbhawna.today

भाजपा से राज्यसभा के पूर्व सदस्य और उद्योगपति...पेज-05

DELHIN/2014/58158

हायलो ओपन: सिंधु और अनमोल खरब...पेज-06



एक नजर

स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने जारी किए स्मारक डाक टिकट

नई दिल्ली। स्तन कैंसर के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को डाक विभाग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विशेष स्मार्क डाक टिकट जारी किया है। इन स्मार्क डाक टिकटों का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सिलिला श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्तन कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों की रोकथाम और समय पर पहचान के लिए आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने और बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज न करने की अपील की। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश में मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा (सर्विकल) कैंसर की जांच के तहत अब तक 86.97 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें से लगभग 5.50 लाख लोग वर्तमान में उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कैसेर की समस्या रहती पहचान होने से उपचार की संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। इसलिए नियमित जांच, सही जानकारी और समय पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख सलिला श्रीवास्तव ने कहा, 'महिलाओं की स्वास्थ्य स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र की नींव है।' उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने तथा स्तन कैसेर के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सरकारी संस्थाओं, स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। इस पहल के माध्यम से डाक टिकटों को जन-जागरूकता का माध्यम बनाकर स्तन कैसेर की रोशनी में, समय पर जांच और उपचार के महत्व का संदेश देशभर में पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

आईडीबीआई बैंक पर सीतारमण का राहुल गांधी को जवाब

नई दिल्ली, एजेसी। विम मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'कांग्रेस बैंक बनाती है, मोदी सरकार बेचती है' वाली टीपणी पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों के समय बैंकों और वित्तीय संस्थानों का इस्तेमाल अपनी निजी संस्था के रूप में किया गया था और बैंककर्मियों पर दबाव डाल कर अपने चहेते को कर्ज दिलवाये जाते थे। विम मंत्री ने कहा कि आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक पुनर्गठन में सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है और इसे सरकार स्पष्ट कर चुकी है। विम मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आजादी के कृष्ण समय बाद से ही कांग्रेस के समय के विभिन्न चर्चित 'वित्तीय घोटालों' का उल्लेख करते हुए कहा, 'हम सभी जानते हैं कि कैसे कांग्रेस ने (अपने समय में) बैंकों और वित्तीय संस्थानों का इस्तेमाल अपनी निजी संस्थाओं के रूप में किया है और विवेकपूर्ण ऋण मानकों को दरकिनार करते हुए बैंक कर्मचारियों पर अपनी इच्छा के अनुसार कण देने का दबाव डाला है। उन्होंने इस संबंध में कहा कि 1957 में, कांग्रेस नेताओं के प्रभास के कारण हरिदास मुंदड़ा को एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) से पैसा मिला। 1976 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने एसबीआई (स्टेट बैंक) के अध्यक्ष आर.के. तलवार को इस बात पर हटा दिया कि उन्होंने संजय गांधी के करीबी से जुड़ी एक कंपनी के लिए शर्तों में डील देने के राजनीतिक दबाव को मानने से इनकार कर दिया था।

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना हंड

आवाज़ अधिकार की

आवाज़ अधिकार की

**बदरीनाथ से उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर
दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत छह लोगों की मौत**

ज्योतिर्मठ, एजेंसी। उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार को बदरीनाथ धाम से देहरादून के सहस्रनाथ लॉट रहा ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत उसमें सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर ज्योतिर्मठ तहसील के चाई गांव के ऊपर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सेना की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी छह लोगों की मृत्यु की पुष्टि की। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी की ओर से शुक्रवार शाम 5:30 बजे जारी प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर ने बदरीनाथ धाम से देहरादून स्थित सहस्त्रनाथ हेलीपैड के लिए दोपहर करीब 1:12 बजे उड़ान भरी थी। इसके बाद करीब दो बजे ज्योतिर्मठ तहसील के चाई गांव के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने हेलीकॉप्टर में पायलट समेत सभी सवार सभी छह लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु होने की पुष्टि की।

हादसे की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन, सेना, पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीमों सक्रिय खाना हुई थीं। सेना की नौवीं स्वतंत्र माउंटन विंग्रेड के अधिकारियों से अनुशासन की ओर से जारी मृतकों की सूची के प्रशासन, हादसे में पायलट एचएस सुभवाल के अलावा यात्री अरुण सालुंके, हिमाचल नटवाज, प्रताप बच्चिहल्ली निंगराजन, सुधीर के. और शंकरगोड़ा वीबी की मौत हुई है। पांचों यात्रियों को कर्नाटक कानिवासी बताया गया है। उतराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूसीडीए) के अनुसार, हेलीकॉप्टर का काला जड़ान वीटी-एचसीएसम् था। उसने बदरीनाथ से सहस्त्रधारा के लिए उड़ान भरनी थी। जोशीमठ घाटी के ऊपर उड़ान के दौरान उसका संपर्क टूट गया और ट्रैकिंग सिस्टम भी उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाया। सूचना मिलते ही भारतीय सेना, चमोली जिला प्रशासन और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीमों

A white helicopter with orange accents is flying over a rugged, mountainous landscape. The helicopter is positioned in the upper center of the frame, with its main rotor blades blurred due to motion. The background features steep, rocky mountains under a cloudy sky. The overall scene suggests a high-altitude environment, possibly for rescue or transport.

खोज एवं बचाव अभियान के लिए रवाना की गई एहतिगत के तौर पर यू.सी.एडीए ने ट्रांस भारत एविएशन के सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बाद में सेना की टीम ने ज्योतिर्मठ तहसील के चाई गांव के पास दुर्घटनास्थल पर पहुँचकर हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी छह लोगों की मौत की पुष्टि की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई जनहानि पर दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति

संवेदना जाता। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाए। साथ ही जिला प्रशासन को भ्रातिवित्त परिचारों को हर्षभंग सहजता उपलब्ध कराने और आवश्यक राहत एवं अन्य व्यवस्थाएँ तत्परता से सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने भी हेलीकोप्टर दुर्घटना में दुर्ग जहाज पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति का कामना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की।

अब वायु सेना प्रमुखों को रेस कोर्स एयर फ़ोर्स स्टेशन में दिए जाएंगे गार्ड ऑफ ऑनर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली में रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन की जमीन के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारतीय वायु सेना के मौजूदा प्रमुख और नवनियुक्त प्रमुख के लिए हाई प्रोफाइल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को 31 अक्टूबर को विदाई के दिन और आशुतोष दीक्षित को वायु सेना प्रमुख बनने के बाद एक नवंबर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यह पहली बार है जब लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के घर के सामने एयर फोर्स स्टेशन पर यह कार्यक्रम होगा।

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को देश के लिए उनकी 42 साल की शानदार सेवा के बाद 26 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदाई दी। रक्षा मंत्री को ने उनकी शानदार सेवा, बेहतरीन लीडरशिप और देश के लिए उनके अनमोल योगदान की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को सफलतापूर्वक पूरा करने और भारतीय वायु सेना की क्षमताओं को मजबूत करने में एयर चीफ मार्शल की अहम



भूमिका को माना। उन्होंने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को उनके भविष्य के कामों के लिए शुभकामनाएं दीं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह 31 अक्टूबर को बहादुरों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल पर पुष्पचक्र चढ़ाएंगे और रिटायर होने से पहले नई दिल्ली के एयर फॉर्स स्टेशन में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे। वह 25 महीने के कार्यकाल के बाद 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित कल ही दोपहर में नए एयर चीफ ऑफ स्टफ का पद संभालेंगे।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार
1.27 अरब डॉलर घटकर
719.75 अरब डॉलर पर

नई दिल्ली। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अक्टूबर को समाप्त होने पर भी 1.27 अरब डॉलर और अधिक बढ़ गया है। पिछले 719.75 अरब डॉलर बढ़ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार छठे हफ्ते गिरावट दर्ज हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि इससे पहले 16 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.01 अरब डॉलर घटकर 721.01 अरब डॉलर रहा था।

आकड़ों के अनुसार 23 अक्टूबर को समाप्त हफ्ते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक अमेरिकी मुद्रा परिसंचित 593.25 अरब डॉलर बढ़कर 593.25 अरब डॉलर हो गई। आरबीआई ने कहा कि इस अवधि में भंडार का मूल्य 2.65 अरब डॉलर घटकर 103.15 अरब डॉलर रह गया। साथ ही विशेष आह्वान अधिकांश (एसडीआर) 27 लाख डॉलर बढ़कर 18.60 अरब डॉलर हो गए।

आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को रिश्ता टूटने के बाद दुष्कर्म नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने रिश्तों में खटास आने के आधार पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जब भी व्यक्ति को बीच किसी रिश्ते के टूटने में आपसी सहमति से शारीरिक संबंध ब्रेक हो तो सफ़र रिश्ता खराब होने लगता है। अक्सर खलत हो जाने के कारण उन संबंधों में खलौट आती है। न्यायाधीशों ने कहा कि रिश्ते के टूटने के बाद में दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता।

जस्टिस बी.वी. नागल्ला को संभलता वाली बेंच ने केरल के एक न्यायाधीश को दुर्घटना और धोखाधड़ी के दोषों में से बुरी करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि संभलता से ही धोखा या छल से सम्बन्धित कानून कानून अलग बात है लेकिन यह खतम करना के बाद पुराने फैसलों केवल 'रूढ़तावा' होने को न्यायाधीश राधिक ममला बनाने का आधार बन गया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि हर दूसरे को दुर्घटना के सम्बन्धित से आरोपित की व्यक्तिगत त्रुटि और प्रतियुक्त धूमिल होता है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति

को सिर्फ इस डर से रिश्ते में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि अलग होने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हो सकता है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि हर असफल रिश्ते को दुष्कर्म का मामला बना देने से इस गंभीर अपराध (यौन हिंसा) की वास्तविकता और कानूनी गंभीरता कमजोर होती है। इन मामले के आरोपित संतोष कुमार एन.पी. ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें उसकी 'डिस्चार्ज याचिका' और उसके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। पीड़िता का आरोप था कि आरोपित ने अपनी पहली शादी को छिपाकर उससे दूसरी शादी की। पीड़िता का आरोप था कि आरोपित ने उसे यह विश्वास दिलाकर कि उनकी शादी वैध है, धोखे से उसके साथ पति-पत्नी की तरह रहा। आरोपित ने अपनी पहली शादी के कायम रहते हुए ही दूसरी शादी कर ली थी।

दिल्ली की रैली में शामिल होने आ रहे लोगों को रोकने की कोशिश: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को प्रस्तावित विपक्ष की रैली से पहले दूसरे राज्यों से यहां आ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब समेत कई राज्यों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों को यहां आने से रोका जा रहा है।



राज्यों से दिल्ली आ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचने वाले लोगों की संख्या और रास्ते में रोके गए लोगों की संख्या से देश में चल रही स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि लोगों में काफी गुस्सा और भावनात्मक पीड़ा है, क्योंकि लाखों लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया

है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों के वोट अडानी, आमोनी, नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और भगवान को फायदा पहुँचाने के लिए चोरी किए जा रहे हैं। ये अलग-अलग विरोध प्रदर्शन नहीं हैं, बल्कि एक ही आंदोलन का हिस्सा हैं। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है और विरोध करना चाहने वाले सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस संपद ने कहा कि यह लड़ाई संविधान, भारत के विचार और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए है। वोट देने का अधिकार हर भारतीय की आवाज है और विपक्ष इसी अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हुआ है। राहुल गांधी ने बताया कि आज होने वाले इसी तरह के कार्यक्रम (इंडी गलथेन्स की बैठक) को शनिवार के लिए टाल दिया गया है।

नई दिल्ली, एजेन्सी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की भविष्य की आर्थिक वृद्धि में भू-स्थानिक (जियोस्पेशियल) तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार और उद्योग के बीच मजबूत साझेदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भू-स्थानिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने का मंत्र है—'सूचना बनाना, निवेश करना और अपनाना'। डॉ. जितेंद्र सिंह शुक्रवार को नई दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ इंडिया) की ओर से आयोजित 'विकसित भारत 2047' के लिए भू-स्थानिक अर्थव्यवस्था का सह-निर्माण: सरकार और उद्योग के बीच तालमेल' विषयक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न प्रदर्शकों से बातचीत की।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सरकार के वरिष्ठ

अधिकारियों और उद्योग जगत के प्रति के साथ एक गोलमेज चर्चा में भी शामिल। मंत्री ने कहा कि भू-स्थानिक अब केवल नक्शे बनाने और सर्वेक्षण सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि के लिए एक रणनीति में संसाधन बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र नेतृत्व और प्रोत्साहन से पिछले 12-15 क्षेत्र में कई व्यापक सुधार किए गए सुधारों को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा

और साहस की ज़रूरत थी। उन्होंने देहरादून में स्थित भारतीय सर्वश्रेष्ठ विभाग के पर्सनर की अपनी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले सर्वश्रेष्ठ कार्य में काफी शारीरिक श्रम लगता था, लेकिन आज इस क्षेत्र में कंप्यूटिंगिंग और आधुनिक तकनीक का ज्ञान रखने वाले लोग युवा पेशेवरों की आवश्यकता हैं। मंत्री ने कहा कि भू-स्थानिक कारोबार में अब बाजार विस्तार करने, व्यावहारिक कारोबारों में डॉलर तैयार करने और स्टार्टअप तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम

उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी मजबूत करनी होगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति-2022 ने इस क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीकों को अपनाने के लिए एक खुला ढांचा उपलब्ध कराया है। इसमें भू-स्थानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती तकनीकों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम की गति और प्रदीप्ता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मंत्री ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर काम करने की संभावनाएँ तालिशने का आग्रह किया। उन्होंने सर्वेयर जनरल को निर्देश दिया कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जाएँ ताकि उन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की क्षमताओं और उपलब्ध तकनीकों की जानकारी मिल सके।

डीयू में युवा संगम : तमिलनाडु के 55 सदस्यीय युवा दल ने दिल्ली की विरासत और संस्कृति को जाना

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संगम के सातवें चरण के तहत हरियाणा और पंजाब की सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। शिक्षा मंत्रालय की 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के अंतर्गत आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रम में तमिलनाडु से आए 55 सदस्यीय युवा दल को दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और परंपराओं से परिचित कराया जा रहा है। कार्यक्रम के चौथे दिन दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित सांस्कृतिक समारोह में श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और अदिति महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने पंजाब के पारंपरिक लोकनृत्य गिद्धा सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने हरियाणा और पंजाब की सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययनरत तमिलनाडु के विद्यार्थियों ने भी अपने पारंपरिक लोकनृत्य प्रस्तुत किए। इससे सांस्कृतिक आदान-प्रदान के इस आयोजन में दक्षिण और उत्तर भारत की लोक परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला।

गांधी भवन के निदेशक और युवा संगम के नोडल अधिकारी प्रो. केपी सिंह ने तमिलनाडु से आए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि वे किसी अलग स्थान पर नहीं आए हैं, बल्कि भारत के एक



सुंदर हिस्से से दूसरे हिस्से में आए हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में भाषाएं और अभिव्यक्तियां भले ही अलग हों, लेकिन देश और उसके लोग एक हैं। यही भारत की खूबसूरती है। उन्होंने तमिलनाडु के देश की संस्कृति में योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि तमिल भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में शामिल है और इसमें समृद्ध साहित्य, शास्त्रीय संगीत, भक्ति तथा विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराएं विद्यमान हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से दिल्ली प्रवास के दौरान कम से कम पांच पक्के मित्र बनाने और उनके साथ संर्गर्क बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक

नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश से प्रेम करे, उसे गहराई से जाने और उसके विकास में योगदान दे। युवा संगम महज एक यात्रा नहीं, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों को भाषाई और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का महत्वपूर्ण अभियान है। गांधी भवन के संयुक्त निदेशक प्रो. हंसराज सुमन ने कहा कि युवा संगम केवल एक यात्रा नहीं बल्कि भारत को जीने का अनुभव है। जब हरियाणा का युवा तमिलनाडु की भाषा सीखेगा और पूर्वोत्तर का युवा दिल्ली की विरासत को जानेगा, तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि भारत की साझा संस्कृति

हर राज्य में मौजूद है और इसकी विशेषता है कि इसमें हर कोई सहज रूप से रच-बस जाता है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने हरियाणा और पंजाब की एकता का परिचय दिया। वहीं, तमिलनाडु से आए विद्यार्थियों और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक-दूसरे की संस्कृति से बहुत कुछ सीखा है। इस दौरान तमिलनाडु के विद्यार्थियों को दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों का भी भ्रमण कराया गया। दल ने लाल किला, कुतुब मीनार, राष्ट्रीय संग्रहालय और इंडिया गेट सहित विभिन्न स्थलों का दौरा किया। इसके अलावा दिल्ली हाट, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज और अन्य स्थानों पर भी विद्यार्थियों को ले जाया गया। कार्यक्रम के तहत खाद्य महोत्सव, हस्तकला प्रदर्शनी, भाषा संगम और 'मेरी संस्कृति, मेरा गौरव' विषय पर युवा संवाद का आयोजन भी किया गया। इस सात दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में केंद्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के 55 युवा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से गठित टीम के शिक्षक इन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रो. चारू कालररा, प्रो. मनोज कुमार कैन, डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह, डॉ. अनिरुद्ध कुमार सुधांशु, डॉ. मनीष कुमार, डॉ. आलोक कुमार, डॉ. अनवर जहां, डॉ. अनंथिवासुदेवन, डॉ. बसंता वी. गोरी सहित विभिन्न कॉलेजों और विभागों के शिक्षक उपस्थित रहे।

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर अब मिलेगी कोच में भीड़ की जानकारी

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और डिब्बों में भीड़ को संतुलित करने के लिए पिंक लाइन पर वास्तविक समय में कोच में यात्रियों की संख्या की जानकारी देने वाली सुविधा शुरू कर दी है। इसके तहत अब यात्री प्लेटफॉर्म पर लगी सूचना प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन के माध्यम से पता लगा सकेंगे कि ट्रेन के किस डिब्बे में कितनी भीड़ है। इससे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार काम भीड़ वाले डिब्बे का चयन करने में मदद मिलेगी। इससे पहले यह सुविधा मैजेंटा लाइन पर उपलब्ध थी, जहां वर्ष 2022 से यात्रियों को प्रत्येक डिब्बे में भीड़ की स्थिति की जानकारी दी जा रही है।

इस व्यवस्था के उपयोगी परिणामों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अब इसका विस्तार पिंक लाइन पर भी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने से पहले ही प्रत्येक डिब्बे में भीड़ का अनुमान मिल सकेगा। इसके लिए स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगी यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। ट्रेन के आने से कुछ समय पहले स्क्रीन पर अलग-अलग डिब्बों में यात्रियों की संख्या के अनुपात से संबंधित जानकारी प्रदर्शित होने लगींगी। इससे यात्रियों को यह तय करने में आसानी होगी कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर किस स्थान पर

खड़ा होना चाहिए। विशेष रूप से कार्यालय जाने और लौटने के समय, जब मेट्रो में यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है, यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। इस व्यवस्था में मेट्रो के प्रत्येक डिब्बे में लगाए गए भार संवेदकों की सहायता ली जाती है। ये संवेदक डिब्बे के वर्तमान भार को मापते हैं और उसकी तुलना डिब्बे के खाली भार से करते हैं। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसमें यात्रियों की संख्या और भीड़ के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद संबंधित जानकारी को प्लेटफॉर्म पर लगी सूचना प्रदर्शन प्रणाली तक पहुंचाया जाता है, जहां यात्री ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे में भीड़ की स्थिति देख सकते हैं। पिंक लाइन पर इस व्यवस्था को लागू करना तकनीकी दृष्टि से चुनौतीपूर्ण था। इसका कारण इस मार्ग का वृत्ताकार स्वरूप और विभिन्न खंडों के बीच आंकड़ों का समन्वय करना है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने इस व्यवस्था के माध्यम से यात्रियों को अधिक उपयोगी और समयानुकूल जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यात्रियों को पहले से ही पता चल सकेगा कि किस डिब्बे में अपेक्षाकृत कम भीड़ है। इससे वे अधिक भीड़ वाले डिब्बों में चढ़ने से बच सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार स्थान चुन सकते हैं।

सत्या शर्मा ने स्थायी समिति की बैठक में 924 करोड़ की सड़क सफाई योजना और बैरियर मुक्त टोल व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी

शबाणा बेगम , सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आज स्थायी समिति की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 90 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की तैनाती, राजधानी के 126 प्रवेश बिंदुओं पर बैरियर मुक्त टोल वसूली व्यवस्था लागू करने और जन-स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को भरने से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख हैं। बैठक में पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षदों को अपने-अपने वार्ड की समस्याओं और सुझाव रखने का पूरा अवसर दिया गया। पार्षदों ने सफाई व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, सफाई कर्मचारियों की कमी, पार्कों के रखरखाव और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। सत्या शर्मा ने कहा कि स्थायी समिति लोकतांत्रिक संवाद और जनहित के मुद्दों पर सार्थक चर्चा का महत्वपूर्ण मंच है। बैठक में पार्षदों की ओर से उठाए गए सभी विषयों को गंभीरता से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य केवल प्रस्ताव पारित करना नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना भी है।

वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 924 करोड़ की योजना

सत्या शर्मा ने निगम की सड़कों पर 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें (एमआरएसएम) तैनात करने की करीब 923.57 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इन मशीनों के माध्यम से अगले 10 वर्षों तक सड़कों की सफाई की जाएगी। योजना का उद्देश्य सड़कों पर जमा धूल और वाहनों की आवाजाही से उड़ने वाले धूलकणों को कम करना है। छोटी क्षमता वाली मशीनें इलेक्ट्रिक होंगी, जबकि बड़ी क्षमता की मशीनों के लिए इलेक्ट्रिक या सीएनजी का विकल्प रखा गया है। इस परियोजना को तीन पैकेजों में बांटा गया है। पहले पैकेज में 29 मशीनों के लिए लॉयन सर्विसेज लिमिटेड को 369.53 करोड़ रुपये, दूसरे



पैकेज में 28 मशीनों के लिए जीए इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और वीएन इंजीनियरिंग कंपनी के सहसंघ को 368.83 करोड़ रुपये तथा तीसरे पैकेज में 13 मशीनों के लिए जेएस एनवायरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 185.20 करोड़ रुपये का काम देने की स्वीकृति दी गई है। संबंधित एजेंसियों को मशीनों की तैनाती के साथ 10 वर्षों तक उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सड़कों की नियमित और प्रभावी सफाई जरूरी है। आधुनिक मशीनों और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल से सफाई व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली की सीमाओं पर बैरियर मुक्त होगी टोल वसूली

स्थायी समिति अध्यक्ष ने दिल्ली के 126 पथ कर संग्रहण बिंदुओं पर मौजूदा आरएफआईडी व्यवस्था को अपग्रेड कर मल्टी लेन फ्री प्तो (एमएलएफएफ) तकनीक लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नई व्यवस्था में व्यावसायिक वाहनों को पथ कर और पर्यावरण प्रतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) चुकाने के लिए बैरियर पर रुकना नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नवनिर्मित एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 'पवन-डूउसी' का दौरा कर वायु प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए अब केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी पहले से पहचान कर वास्तविक समय में कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियां बंद रखी जाएंगी। मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे जरूरी है कि सटीक, स्थानीय स्तर का डेटा उपलब्ध हो और पूरी व्यवस्था पारदर्शी रहे। 'पवन-डूउसी' इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच डेटा के बंटवारे की समस्या दूर होगी और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान कर कुछ ही मिनटों में कार्रवाई की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना किसी एक एजेंसी या राज्य की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। नए कमांड सेंटर के माध्यम से खेतों में पराली जलाने, उद्योगों से निकलने वाले धुएँ और बिना ढक्के निर्माण स्थलों जैसी गतिविधियों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि निगरानी प्रणाली से मिलने वाले अलर्ट पर बिना देरी के कार्रवाई सुनिश्चित करें। भूपेंद्र यादव ने कहा कि निर्धारित मानकों, वैधानिक निर्देशों या अनुपालन संबंधी शर्तों का उल्लंघन होने पर यह प्रणाली संबंधित एजेंसी को अलर्ट



भेजेगी। इससे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, निर्माणों का पालन नहीं करने वाले स्रोतों और यातायात जाम वाले संवेदनशील क्षेत्रों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था मैनुअल निगरानी और एजेंसियों की ओर से भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर निर्भरता कम करेगी। इससे विभिन्न एजेंसियों के बीच समय-समय मजबूत होगा, नागरिकों की शिकायतों का तेजी से समाधान होगा और प्रदूषण के स्तर में अचानक बढ़ोतरी होने पर तत्काल कदम उठाए जा सकेंगे।

कमांड सेंटर में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य कार्ययोजनाओं की भी निगरानी होगी। इसमें वायु गुणवत्ता, पराली प्रबंधन, वाहन प्रदूषण, निर्माण गतिविधियां, सड़क की धूल, ठोस कचरा प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनरेटर सेट और हरित शवदाह गृहों से जुड़े कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एवं

पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. अमनदीप गर्ग सहित मंत्रालय, आयोग और सीपीसीबी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएक्यूएम का 'पवन-डूउसी' एक डिजिटल कमांड सेंटर है, जो 30 से अधिक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और विभिन्न डेटा स्रोतों को एक मंच पर जोड़ता है। इसमें वायु गुणवत्ता, औद्योगिक उत्सर्जन, मौसम, उपग्रह से प्राप्त जानकारी, कैमरों, वाहनों की आवाजाही, यातायात जाम, नागरिक शिकायतों और नियमों के अनुपालन से जुड़ा डेटा शामिल है। इस प्रणाली में दिल्ली-एनसीआर के 111 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों, 2,300 से अधिक उद्योगों और 3,200 से अधिक सक्रिय निर्माण स्थलों का डेटा भी शामिल किया गया है। यह प्लेटफॉर्म 'पहचान, विश्लेषण और कार्रवाई' के सिद्धांत पर काम करता है। इसके माध्यम से प्रदूषण के स्तर का वास्तविक समय और पुराने आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकेगा।

जन-स्वास्थ्य विभाग के 1066 रिक्त पद भरने के निर्देश

बैक में जन-स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों को भरने से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। विभाग में 14 एंटी मलेरिया अधिकारी, 105 मलेरिया निरीक्षक, 398 सहायक मलेरिया निरीक्षक और 549 एमटीएस (जन-स्वास्थ्य) सहित कुल 1066 पद रिक्त हैं। सत्या शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की कमी से मच्छरजनित बीमारियों को रोकथाम, क्षेत्रीय निरीक्षण और निगरानी संबंधी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने तथा नियमित नियुक्तियों में समय लगने की स्थिति में संविदा या अनुबंध आधार पर भी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।

जोन स्तर पर ही हो समस्याओं का समाधान

सत्या शर्मा ने सभी जोनों के उपायुक्तों को अपने कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने और कर्मचारियों की उपस्थिति एवं कार्यप्रणाली की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचें और आम नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान करें। पार्षदों को अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए बार-बार निगम मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। शिकायतों का निस्तारण जोन स्तर पर ही समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक ऐसा पार्क विकसित करने के निर्देश भी दिए, जहां वर्षा जल संचयन की व्यवस्था हो। इससे वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पार्कों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में उठाए गए जनहित के मुद्दों और पारित प्रस्तावों पर गंभीरता से कार्रवाई करें। संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई की नियमित समीक्षा भी की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है और इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करना होगा।

दिल्ली की प्लानिंग अब एनसीआर को साथ लेकर : एलजी

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे
नई दिल्ली। दिल्ली की आवास, परिवहन, जल निकासी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अब पूरे एनसीआर को ध्यान में रखकर एकीकृत योजना तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर जमीन के इस्तेमाल, आवास और परिवहन ढांचे का विकास किया जाएगा। साथ ही, शहर की सड़कें और सार्वजनिक सुविधाएं महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के अनुकूल बनाई जाएंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को युवा नगर नियोजकों के सेमिनार में शहरी विकास की प्राथमिकताएं गिनाते हुए ये बातें कहीं।

विश्व पर्यावास दिवस, विश्व नगर दिवस और विश्व नगर नियोजन दिवस के अवसर पर आयोजित सेमिनार में उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना बड़ी चुनौती है। आवास, परिवहन, पानी और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। ऐसे में दिल्ली की योजना एनसीआर के व्यापक संदर्भ में बनानी होगी। जमीन के इस्तेमाल और परिवहन ढांचे के बीच बेहतर तालमेल को विकास को व्यवस्थित बनाया जा सकता है।

उपराज्यपाल ने कहा कि केवल किफायती आवासों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि लोगों को घर के आसपास रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। आवासीय क्षेत्रों का विकास इस तरह किया जाना चाहिए कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लोगों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े।

उन्होंने कहा कि जल निकासी, वर्षा जल संचयन और जलाशयों के संरक्षण के लिए एकीकृत योजना तैयार करनी होगी। प्राकृतिक जल निकासी तंत्र को सुरक्षित रखने के साथ विकास कार्यों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। उपराज्यपाल ने कहा कि सड़कें और सार्वजनिक परिवहन महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक होने चाहिए। शहरी नियोजन में लोगों की रोजमर्रा की यात्रा को आसान बनाने पर विशेष ध्यान देना होगा। युवा नगर नियोजकों को जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल मैपिंग और शहरी आंकड़ों का उपयोग बढ़ाने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीक के साथ पेशेवर समझ और स्थानीय जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है। जमीन, आवास और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले तथ्य, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनहित पर आधारित होने चाहिए। कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे।

सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के समर्थन में 1 नवंबर को हरिनगर में भाजपा निकालेगी विरोध मार्च

नई दिल्ली। 1984 के सिख दंगों से प्रभावित परिवारों, समाज और विभिन्न संस्थाओं के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी 1 नवंबर को पश्चिमी दिल्ली के सिख बहुल क्षेत्र हरिनगर में सांकेतिक विरोध मार्च निकालेगी। इसमें हजारों सिख नागरिकों के साथ भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस विरोध मार्च का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी करेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने शुक्रवार को बताया कि 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 1984 तक का समय भारतीय इतिहास में विशेष रूप से सिख समाज के लिए बेहद दुखद और पीड़ादायक रहा है। इन दिनों के दौरान दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों निर्दोष सिखों की हत्या की गई, उनके घरों और दुकानों को लूटा गया तथा आग के हवाले कर दिया गया। 1 नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित रैली पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी के दिन राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को दोबारा स्थापित करने के लिए रैली आयोजित करना सिख समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी की राजनीतिक पुनर्स्थापना से पहले 1984 के दंगों के पीड़ित सिख परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले दस दिनों से दिल्ली के अनेक सिख नेता और सिख संस्थाओं के प्रबंधक भाजपा नेताओं से मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा से इस मुद्दे को समाज के सामने उठाने में सहयोग मांगा है। मल्होत्रा ने कहा कि दिवाली के सप्ताह में कांग्रेस की बड़ी रैली आयोजित होने से दिल्ली के व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हजारों वाहनों के राजधानी में आने से यातायात प्रभावित होने और बाजारों में व्यापार ठप होने की आशंका है। उन्होंने दावा किया कि व्यापारी कांग्रेस नेताओं से रैली को दिवाली के बाद आयोजित करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होने वाले वाहन प्रदूषण संबंधी नियमों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीएस-6 मानक से पुराने बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण रैली में आने वाले वाहनों को लेकर भी स्थिति जटिल हो सकती है। इससे यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर विवाद की आशंका है।

खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग, 20 नवंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट



नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज रूबी अलका गुप्ता ने 20 नवंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता की ओर से वकील गगन गांधी और खरगे को ओर से प्रज्वलन सिंह ने लिखित दलीलें दाखिल दी। इसके पहले 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान खरगे के बयान पेन ड्राइव में न्यायालय में दाखिल किए गए। 14 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें पूरी कर ली गईं। 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखते हुए कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर कानून सम्मत फैसला किया है। इसके पहले 19 सितंबर को खरगे की ओर से इस बात से इनाकार किया गया था कि वो लिखित वचन दें कि वो संघ के खिलाफ कोई भी मानहानिकारक बयान नहीं देंगे। याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने कहा है कि वो संघ का सदस्य होने के नाते खरगे के बयानों से आहत है। उन्होंने खरगे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग की। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में कहा गया है कि खरगे ने 27 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और संघ के बारे में अपमानजनक बयान दिए। याचिका में कहा गया है कि खरगे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में न्यायालय ने सब्जी मंडी पुलिस थाने को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। सब्जी मंडी थाने की पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बयान कर्नाटक में दिए गए हैं और वो सब्जी मंडी थाने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

एक नजर

लोन दिलाने के नाम पर 1.95

लाख की ठगी में दो काबू

गुरुग्राम। लोन दिलाने के नाम पर फीस वसूलकर ठगी करने वाले साइबर ठगों को बैंक खाता बेचने वाले दो आरोपियों को गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 24 अगस्त 2026 को एक व्यक्ति ने थाना साइबर अपराध मानेसर में शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर उसे लोन दिलाने के लिए संपर्क किया। आरोपी ने लोन प्रोसेसिंग, फाइल चार्ज और अन्य शुल्कों के नाम पर पीड़ित से कुल 1,95,662 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए और बाद में फोन बंद कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक खातों की ट्रेल खंगाली तो पता चला कि ठगी की रकम एक ऐसे खाते में गई है जो साइबर ठगों को बेचा गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए थाना साइबर अपराध मानेसर की टीम ने 29 अक्टूबर को उत्तराखंड के हरिद्वार से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान शिवम और अनमोल दोनों निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि जिस खाते में 1,95,662 रुपये की ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी, वह आरोपी अनमोल के नाम पर था। अनमोल ने अपना बैंक खाता अपने साथी शिवम को बेच दिया था। शिवम ने आगे वह खाता साइबर गट गिरोह को उपलब्ध करा दिया, जिसका इस्तेमाल लोन के नाम पर ठगी की रकम लेने के लिए किया गया। पुलिस अब इन खातों को खरीदने वाले मुख्य साइबर ठगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दोनों आरोपियों से यह पूछताछ जारी है कि उन्होंने और कितने खाते साइबर अपराधियों को बेचे हैं।

क्रेडिट कार्ड रिवाइंड पॉइंट के नाम पर 1.90 लाख की ठगी

गुरुग्राम। क्रेडिट कार्ड के रिवाइंड पॉइंट रिडीम कराने के नाम पर लिंक भेजकर 1.90 लाख रुपये ठगने वाले गिरोह के चार आरोपियों को साइबर क्राइम पूर्व थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। 24 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना साइबर अपराध पूर्व में शिकायत दी थी कि उसे क्रेडिट कार्ड के रिवाइंड पॉइंट रिडीम करने के नाम पर एक लिंक भेजा गया। लिंक पर क्लिक करते ही उसके बैंक खाते से 1,90,000 रुपये निकाल लिए गए। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस टीम ने 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में छपेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान आलोक कुमार निवासी गांधे सेसा जिला झांसी, शैलेंद्र सिंह उर्फ निंदू निवासी गांव महाराजगंज जिला झांसी, कृष्ण कांत निवासी जिला जालौन व सौरभ अली निवासी जिला जालौन के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि ठगी की पूरी रकम आरोपी आलोक कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आलोक ने अपना बैंक खाता 8,000 रुपये कमीशन के बदले शैलेंद्र और कृष्ण कांत को दिया था। उन दोनों ने आगे वही खाता कमीशन पर सौरभ अली को दे दिया था, जिसका इस्तेमाल ठगी के लिए किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को 28 अक्टूबर को गिरफ्तार करने के बाद 29 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी सौरभ अली को एकदिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि बाकी तीन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है।

दुकान जाने के लिए निकली किशोरी गायब

नोएडा। गढ़ी चौखंडी गांव से 15 वर्षीय किशोरी नौ दिन से लापता है। काफ़ी तलाश के बाद भी उसका सुराग नहीं मिलने पर परिजनों ने गुस्वारा को थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर किशोरी की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मूसरूप से अलीगढ़ के चंडौस क्षेत्र की रहने वाली महिला परिवार के साथ गढ़ी चौखंडी गांव में करारये पर रहती है। वह एक फैक्टरी में नौकरी करती है। उनकी 15 वर्षीय बेटी 22 अक्तूबर की शाम करीब सात बजे दुकान पर जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मां ने किशोरी को बहलाकर ले जाने की आशंका जलाई। मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से किशोरी की तलाश की जा रही है।

शिक्षा-चिकित्सा में छूट दिलाने के लिए आंदोलन का ऐलान

ग्रेटर नोएडा। करषान फ्री इंडिया संगठन की शुक्रवार को सेक्टर चाई-4 में एक बैठक हुई। इसमें गौतमबुद्ध नगर के अंतर्गत आने वाले तीनों प्राधिकरणों के क्षेत्रों में निजी बिल्डरों द्वारा किए जा रहे भूजल दोहन को रोकने तथा लीज डीड में अंकित शर्तों के अनुसार स्थानीय किसानों को शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में छूट दिलाने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय एवं अलोक नागर ने कहा कि जल्द ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अंतर्गत निजी बिल्डरों द्वारा किए जा रहे भूजल दोहन पर रोक लगाने तथा स्थानीय किसानों को उनके अधिकार दिलाने के लिए व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा में स्थानीय किसानों की जमीन पर स्थापित स्कूलों एवं अस्पतालों में किसानों को मिलने वाली शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं एवं छूट को प्रभावी रूप से लागू कराने की मांग भी आंदोलन का प्रमुख मुद्दा रहेगा।

नेशनल हाईवे बना ऑटो स्टैंड! एच-9 पर रोज लग रहा भीषण जाम

साहिबाबाद। एनएच-9 पर लगातार लग रहे जाम से आम आदमी परेशान है लेकिन दो जिलों की यातायात पुलिस को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा लगाता है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि ऑटो चालकों का राज चलता है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि यहां की हकीकत बयां कर रही है। एनएच-9 ऑटो चालकों की मनमर्जी से जाम लग रहा है और लोग इससे परेशान हो रहे हैं, लेकिन यह समस्या पुलिस को दिखाई नहीं दे रही है।

हाइवे पर कई प्वाइंट्स पर पुलिसकर्मियों की तैनाती तो है लेकिन वह ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते जबकि आम वाहन चालक के चालान करते हैं। जाम लगने की स्थिति में ये मूकदर्शक बने रहते हैं। एनएच-9 पर नोएडा सेक्टर 62 कट और इंदिरापुरम साया गोल्ड सोसायटी के सामने ऑटो चालक सबसे अधिक परेशानी का सबब बन रहे हैं। यहां ये लोग बेलगाम हैं, इन पर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। ऑटो



चालकों की मनमर्जी के कारण पूरा मार्ग धिर जाता है और वाहन चालकों को निकलने में दिक्कत होती है। सेक्टर 62 कट पर करीब 200 मीटर पहले से ऑटो चालकों की लाइन शुरू होती है और कट बन रहे हैं। यहां ये लोग बेलगाम हैं, इन को ये लोग पूरी तरह से घेरे रहते हैं। कट पार करने के बाद भी यही हाल है। ऑटो

चालकों कई-कई लेन में खड़े होकर जाम लगाते हैं। वहीं साया गोल्ड के पास रोडवेज बसों को बेरिकेडिंग के भीतर खड़ा कराया जाता है लेकिन इसके बाहर ऑटो चालक जाग्रा को घेरे खड़े रहते हैं। इन दोनों स्थानों पर यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती तो की गई है लेकिन, इनकी

गुरुग्राम: भूजल स्तर गिर रहा, कम पानी में तैयार फसलों को दें प्राथमिकता: राव इंद्रजीत सिंह

गुरुग्राम। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे गिरते भूजल स्तर और जल संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों पर निर्भरता कम कर मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों को अपनाने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। यह बात उन्होंने शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र शिकोहपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी किए जाने पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में कही।

इस अवसर पर गुजरात के बनसाकांडा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया। कार्यक्रम में पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, मानेसर की मेयर डॉ. इंद्रजीत यादव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि फसल विविधीकरण से न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और किसानों की आमदनी के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखना हम सभी की

सामूहिक जिम्मेदारी है और किसानों की जागरूक भागीदारी से ही टिकाऊ कृषि व्यवस्था का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य कृषि को पारंपरिक तौर-तरीकों से आगे बढ़ाकर आधुनिक, तकनीक आधारित और टिकाऊ खेती के रूप में विकसित करना है, ताकि किसानों की आय में वृद्धि के साथ उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़े। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी पहल के माध्यम से जल के कुशल उपयोग और सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, खाद्य तेलों और दालों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष मिशन शुरू किए गए हैं, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और घरेलू किसानों को उत्पादन के नए अवसर मिलें। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के माध्यम से किसानों को रसायन मुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की समृद्धि, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास का आधार है।

नूंह में अवैध औद्योगिक गतिविधियों पर प्रशासन सख्त, जिलाधीश ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश



नूंह,एजेसी। नूंह जिले में अवैध औद्योगिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और पर्यावरण संरक्षण के साथ आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिलाधीश अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आवासीय एवं कृषि क्षेत्रों में प्लास्टिक और अन्य कचरा जलाने तथा बिना अनुमति औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ऐसी

गतिविधियों के लिए अवैध रूप से बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार नूंह, पुन्हाना, तावड़, नगीना, फिरोजपुर झिरका, इंदी और पिनगवां सहित जिले के विभिन्न गांवों एवं क्षेत्रों में अवैध औद्योगिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। इन गतिविधियों से न केवल अन्य कचरा जलाने तथा बिना अनुमति औद्योगिक गतिविधियां संचालित करने पर रोक लगा दी है। इसके चलते लोगों को परेशानी

का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विभागों और सक्षम प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति एवं आवश्यक स्वीकृति के बिना कोई भी व्यक्ति या औद्योगिक इकाई प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेगी। आवासीय और कृषि क्षेत्रों में प्लास्टिक सहित अन्य कचरा जलाने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सोसाइटी की 23वीं मजिल की बालकनी में फूल तोड़ते समय पिता-पुत्र नीचे गिरे, मौत

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की महगुन मायबुड सोसाइटी की 23वीं मंजिल से नीचे गिरने से केंद्रीय सचिवालय के एक अधिकारी और उनके बेटे की मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़ते वक्त यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद से इकलौते बेटे और पति को खोने वाली महिला अधिकारी का रो-रोकर बुरा हाल है।

बिसरख कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में 40 वर्षीय रणदीप पात्रा अपनी पत्नी अमृता श्रीमणि और 11 साल के बेटे आरव पात्रा के साथ रहते थे। रणदीप पात्रा दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी भी केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन अफसर हैं। परिवार के लोगों को शुक्रवार की सुबह खादू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जाना था, इसलिए सभी सुबह 4:00 बजे सो कर उठे थे। रणदीप ने अपने बेटे आरव को मंदिर में पूजा के लिए बालकनी में लगी बेल से फूल तोड़ने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक आरव बालकनी में रखी छोटी सीढ़ी पर



चढ़कर फूल तोड़ने लगा। बारिश होने की वजह से सीढ़ी फिसल गई। इसी बीच आरव नीचे गिर गया। पिता रणदीप ने बेटे को बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों नीचे गिर गए। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच की इस घटना की सूचना मिलने पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीण रंजन सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया। डीसीपी ने बताया कि उन्होंने रणदीप पत्नी से बातचीत की है। रणदीप की पत्नी ने बताया कि फूल तोड़ने के दौरान यह घटना हुई। पुलिस ने इस मामले में आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से भी बातचीत की।

मौजूदगी का कोई लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। पुलिसकर्मियों का खौफ ऑटो चालकों में नहीं दिखाई देता।

पुलिस कभी ऑटो को मार्ग से हटाती भी है तो ये दोबारा मार्ग घेरकर जाम लगाते हैं। यही हाल इंदिरापुरम की तरफ कनावनी कट और ठीक इसके विपरीत नोएडा में छिज़ारसी कट का भी है। यहां भी पुलिस की जगह ऑटो चालकों का साम्राज्य चलता है और उनकी मनमानी से आम आदमी जा से जुझने का मजबूर है। त्योहारी सीजन में यातायात का दबाव तो बढ़ा लेकिन एनएच-9 पर यातायात पुलिसकर्मियों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ। इस कारण प्रतिदिन जाम लग रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस ने त्योहारों को लेकर बड़े-बड़े दावे तो किए लेकिन सब हवा-हवाई साबित हुए। आने वाले समय में यातायात का दबाव और बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में अतिरिक्त यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती जरूरी है।

बागपत में ‘पोस्टर गैंग’ का पर्दाफाश, दो महिला समेत 6 अभियुक्त गिरफ्तार

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की थाना साइबर क्राइम ने दीवारों पर पंपलेट चिपकाकर फर्जी लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ‘पोस्टर गैंग’ का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर नैथला मोड़ के पास से दो कारों को घेरकर चार शाशिर और दो महिला समेत छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

क्षेत्राधिकारी रोहन चौरसिया ने बताया है कि यह गैंग ‘दीपावली ऑफर’ के तहत आधार और पैन कार्ड पर कम ब्याज पर 01 लाख से 10 लाख तक बिजनेस लोन’ के आकर्षक पंपलेट बड़ौत और अन्य कस्बों में चिपकाते थे। लोन लेने वाले भोले-भाले लोगों को फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस और टैक्स के नाम पर फर्जी बैंक खातों में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कराते और फिर मोबाइल बंद कर ठगी करते थे। पूछताछ में पता चला कि गैंग बिजनौर में नया ऑफिस खोलकर वहां भी ठगी की तैयारी में था। एनसीआरपी पोर्टल पर गैंग के खिलाफ सात साइबर फ्रांड शिकायतें दर्ज हैं। इन लोगों ने मंरूपुर, शाहपुर,



जानसठ, मुजफ्फरनगर और लोहारी, बागपत में 7350 से 57,600 रुपये तक की ठगी की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में लोकेश उर्फ गुड्डू, रवि, अजीत, अमित और दो महिला अपराधी शामिल

है। पकड़े गए आरोपितों के पास से 15 हजार फर्जी पंपलेट और 20,200 रुपये समेत अन्य चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों और किये गए अपराधों की जांच कर रही है।

12 साल से फरार हत्यारोपी दो सगे भाई गिरफ्तार

फरीदाबाद। हत्या के मामले में 12 साल से फरार चल रहे दो सगे भाइयों को क्राइम ब्रांच सेंट्रल और थाना तिगांव की टीमों ने अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप तथा विजय कुमार निवासी गांव सिढौला, वर्तमान निवासी खोरी, तावड़ू, मेवात के रूप में हुई है। इस मामले में इनके दो अन्य भाइयों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि वर्ष 2014 में थाना तिगांव क्षेत्र के गांव सिढौला में लड़ाई-झगड़े के दौरान सुमित नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना तिगांव में मामला दर्ज किया गया था। वारदात के बाद से ही संदीप और विजय कुमार गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चल रहे थे। लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचने के चलते दोनों को न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया गया था। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फरीदाबाद पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही थीं।

संस्कृति और स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

गुरुग्राम। हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तकला, हथकरघा उत्पादों और स्थानीय उद्यमशीलता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस और भारत पर्व में प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस बारे में जिला एमएसएमई केंद्र गुरुग्राम की ओर से जिले में उत्पादों के निर्माताओं से भाग लेने का आह्वान किया गया है। इच्छुक जिला एमएसएमई केंद्र गुरुग्राम से जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। एमएसएमई विभाग के संयुक्त निदेशक रमनदीप नैन ने बताया कि गुजरात के एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक प्रस्तावित कार्यक्रम में हरियाणा के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों में विशिष्ट पहचान और बाजार की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे आयोजनों से उन्हें अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, नए बाजारों तक पहुंच बनाने और संभावित खरीदारों एवं व्यापारिक संस्थानों से

सोधे जुड़ने में मदद मिलती है। हरियाणा की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय विनिर्माण क्षमता हमारी सांस्कृतिक पहचान के साथ रोजगार व स्वरोजगार का भी महत्वपूर्ण आधार हैं। राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में भागीदारी से स्थानीय कारीगरों और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, विशेषता और नवाचार प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने के साथ स्थानीय उद्यमों को नई व्यावसायिक संभावनाएं भी प्राप्त होंगी। रमनदीप नैन ने इच्छुक बुनकरों, कारीगरों एवं उत्पाद निर्माताओं से अपील की कि वे अपने उत्पादों का निवरण, संबंधित जिले का नाम, उत्पादों से जुड़ी जानकारी, लाइव प्रदर्शन की संभावित गतिविधियों, प्रतिभागियों की संख्या तथा संपर्क विवरण जिला एमएसएमई केंद्र गुरुग्राम को जल्द उपलब्ध कराएं, ताकि उनकी भागीदारी के बारे में एमएसएमई निदेशालय हरियाणा व संबंधित विभागों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जा सके।

गुरुग्राम विवि में शुरू हुए सुकून क्लीनिक व शोध केंद्र

गुरुग्राम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) संजय कौशिक ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में मनो-सुकून मानसिक कल्याण क्लिनिक का औपचारिक उद्घाटन किया। इसी अवसर पर उन्होंने दो महत्वपूर्ण शोध केंद्रों सेंटर फॉर प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशन ऑफ सबस्टेंस एब्ज्यूज (सीआईपीएसए) तथा सेंटर फॉर वुमेन्स हेल्थ एंड वेलबींग (सीडब्ल्यूएचडब्ल्यू) का भी शुभारंभ किया। कुलपति प्रो. संजय कौशिक ने बताया कि मनो-सुकून क्लिनिक का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा लोगों को परामर्श, मनोसामाजिक सहायता और नैदानिक सेवाएं प्रदान करना है।

यह क्लिनिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की शीघ्र पहचान, परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने तथा विश्वविद्यालय समुदाय व आम जनमानस में भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा। क्लिनिक में अनुभवी मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टीम सेवाएं प्रदान करेगी। परामर्श लेने के इच्छुक व्यक्ति विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से देश के अनुभवी मनोचिकित्सकों तथा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।



बीपीएल कार्ड धारकों के साथ-साथ मनोविज्ञान विभाग द्वारा गोद लिए गए दस गांवों और दो झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों को क्लिनिक में निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्ष प्रो.गायत्री रैना ने इस अवसर पर

कहा कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं और मादक द्रव्यों के सेवन का स्थायी समाधान केवल उपचार तक सीमित नहीं हो सकता। समय पर पहचान, प्रभावी परामर्श, पारिवारिक सहयोग और सामाजिक जागरूकता भी समान रूप से आवश्यक हैं।

विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों के महत्वपूर्ण सियासी संदेश

कमलेश पांडे

चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों के मिले-जुले परिणामों में भले ही भाजपा-राजग को बढ़त मिली हो, लेकिन उत्तरप्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा-राजग को विपक्षी दलों द्वारा कीट कटकर मिली है, जबकि कर्नाटक की चारो सीट जीतकर भाजपा राजग ने वहाँ की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को जबर्दस्त सियासी पटखनी दी है। वहाँ, कांग्रेस के सामने संगठनात्मक चुनौती खड़ी हुई है। उसे एक मात्र नागपुरी देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में मिली कांग्रेस को यह जीत इस बात का संकेत है कि सफ़र थोड़ा और भाजपा की अतिवादों दलित-ओबीसी नीतियों से ऊब चुके हैं और कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार को जितवाने से भी उन्हें गुरज नहीं है। यदि राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा की मजबूती और बिहार में जन सुराज का आगाज—बीजेपी-एनडीए को सफ़र थोड़ों की दायसीनातक के दृष्टिगत सावधान कर रहे हैं। भले ही चार राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के नतीजे 28 अक्टूबर 2026 को सामने आए, लेकिन इन मिले जुले परिणामों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारतीय राजनीति की एक दिलचस्प तस्वीर पेश की है। जहाँ भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों ने कुल 28 सीटों में से 16 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को एक मात्र सीट मिली है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटों जीतकर अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराई, तो बिहार में जन सुराज को पहली सफलता मिली। महाराष्ट्र में भी मुकाबला पूरी तरह एकरापा नहीं रहा और भाजपा नीत महायुति गठबंधन को कांग्रेस नीत महा विकास अघाड़ी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार से कीट टक्कर मिली है।

इन नतीजों का महत्व केवल जीत और हार की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दलों की संगठनात्मक क्षमता, स्थानीय नेतृत्व, शक्तिक एवं स्नातक मतदाताओं से जुड़ाव और विपक्षी गठबंधनों के भीतर प्रतिस्पर्धा के बारे में भी संकेत देते हैं। जहां तक चारों राज्यों की चुनावी गणित का प्रवाल है तो यह जान लीजिए कि गत 23 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की विधान परिषदों की कुल 28 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसकी मतगणना 28 अक्टूबर को हुई। उत्तर प्रदेश की 11, बिहार की 8, कर्नाटक की 4 और महाराष्ट्र की 5 यानी कुल 28 सीटों के नतीजे आए। उत्तर प्रदेश की कुल 11 सीटों में से भाजपा को 6 और समाजवादी पार्टी (सपा) को 5 सीटों पर जीत मिली, यानी मुकाबला कांटे का रहा। वहीं, बिहार की कुल 8 सीटों में भाजपा को 3 और जनता दल (यूनाइटेड) को 1 सीट मिली। यानी भाजपा नीत राजग 8 सीटों में से 4 सीटें जितने में कामयाब रहा। जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 1, जन सुराज पार्टी को 1 और निर्दलीय को 2 सीटें मिली हैं। इस प्रकार उम्मीद में भाजपा सबसे अधिक तीन सीटें जीतने वाली पार्टी रही। निर्दलीय अहमदगंवां ने



भी दो सीटें हासिल कीं। इनकी भी पृष्ठभूमि भाजपाई ही रही है।

वहीं, कर्नाटक की कुल 4 सीटों में भाजपा को 3 सीटें और जनता दल (सेक्युलर) को 1 सीट मिली। यहां की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस 0 पर आऊट हो गई। कर्नाटक में भाजपा-जद(एस) गठबंधन ने चारों सीटों जीत लीं। वहीं, महाराष्ट्र की कुल 5 सीटों में भाजपा को 1, शिवसेना (महायुति) को 1, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली। वहीं, महाराष्ट्र विधान परिषद की नागपुर स्नातक निर्वाचन सीट के चुनाव आयोग और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुधाकर कोहले को शिकस्त दी है। चार राज्यों में 16 सीटें जीतना भाजपा और उसके सहयोगियों के लिए संतुष्टात्मक सफलता का संकेत है। विशेष रूप से कर्नाटक में चारों सीटों पर जीत ने विपक्षी गठबंधन के समन्वय और कांग्रेस की स्थानीय चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, इन परिणामों को सीधे विधानसभा चुनावों के जनादेश के बराबर मानना उचित नहीं होगा। भाजपा के सामने अब इस सफलता को व्यापक जनसंपर्क, स्थानीय समस्याओं के समाधान और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़ने की चुनौती है। कांग्रेस द्वारा चारों राज्यों में मात्र एक सीट जीत पाना उसके लिए गंभीर

राजनीतिक सवाल पैदा करता है। खासकर कर्नाटक में उसकी अपनी सरकार है, फिर भी पार्टी किसी सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकती। इसमें तीन संभावित सबक हैं: एक, स्थानीय स्तर पर संगठन और उम्मीदवार चयन की समीक्षा आवश्यक है। दो, शिक्षक एवं स्नातक जैसे विशिष्ट मतदाता वर्गों से निरंतर संपर्क जरूरी है। तीन, गठबंधन की राजनीति के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को भी मजबूत करना होगा। हालांकि, विधान परिषद चुनावों के मतदाता सीमित और विशिष्ट वर्गों से आते हैं। इसलिए इन नतीजों के आधार पर कांग्रेस के समूचे जनधार के बारे में आंशिक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। उत्तर प्रदेश के नतीजे खास महत्व रखते हैं, क्योंकि राज्य में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। भाजपा ने कई सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, लेकिन सपा ने पांच सीटों जीतकर यह दिखाया कि वह विधान परिषद के चुनावों को भी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखती है। सपा को वाराणसी की दो सीटों पर सफलता मिलना भी उल्लेखनीय रहा। इसका सियासी अर्थ यह है कि दोनों दलों को अपने संगठन, स्थानीय नेतृत्व और मतदाता संपर्क पर ध्यान देना होगा। फिर भी, विधान परिषद के सीमित मतदाता वर्ग और विधानसभा के व्यापक मतदाता वर्ग में अंतर है। इसलिए इन नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव को निश्चित संकेत

सुप्रीम कोर्ट ने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया है कि इस साल देश में डिजिटल असेस्ट और साइबर फ्रॉड के कारण जनता ने लगभग आठ सौ करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि गंवाई है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तबाही और टूटे हुए सपनों की दास्ता है, जिन्होंने अपनी जमा-पूजी को सुरक्षित मानकर बैंकों के हवाले किया था। जब कोई अपराधी किसी खाते से करोड़ों रुपये ट्रांसफर करने में सफल हो जाता है, तो यह केवल पीड़ित की सादगी नहीं, बल्कि उस बैंक के सुरक्षा चक्र की पूर्ण विफलता होती है। अदालत ने इसी बिंदु पर प्रहार करते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि यदि किसी खाताधारक के सामान्य व्यवहार या पुराने पैटर्न से अलग कोई 'असामान्य ट्रान्जेक्शन' या सदिग्ध लेनदेन होता है, तो बैंक को उस पर तुरंत अस्थाई रोक लगानी होगी। यह एक ऐसा सुरक्षात्मक कदम है जो अगर पहले से मुस्तैदी से लागू होता, तो आज आठ सौ करोड़ रुपये का यह राष्ट्रीय नुकसान रोका जा सकता था। इस पूरे संगठित अपराध की रीढ़ की हड्डी 'म्यूचुअल अकाउंट्स' यानी वे फर्जी बैंक खाते हैं, जिनका उपयोग साइबर ठग अपनी पहचान छिपाने और पैसे को अलग-अलग खातों में घुमाने के लिए करते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बिना बैंकों के भीतर बैठे कुछ भ्रष्ट तत्वों की मिलीभगत या फिर बैंकों के ढीले रैट्टे के, हजारों की संख्या में फर्जी दस्तावेजों पर खाते खोलना और उनमें करोड़ों का लेन-देन होना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: क्या अब सुधरेंगे फ्रॉड पीड़ितों के हालात?

अशोक भाटिया

भारत में डिजिटल क्रांति ने जहाँ आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है, वहीं इसने एक ऐसे अदृश्य और खोफनाक अपराध-वृत्त को भी जन्म दे दिया है जिसने देश की पूरी बैंकिंग और सुरक्षा व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज के दौर में साइबर फ्रॉड और विशेस रूप से 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी त्रासदियों किसी महामारी की तरह फैल चुकी हैं, जहाँ पलक झपकते ही किसी व्यक्ति की जीवनभर की गाढ़ी कमाई अपराधियों के खातों में चली जाती है। ऐसे माहौल में देश की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट की हालिया रुख न केवल डिजिटल और साइबर फ्रॉड के पीड़ितों के हक में एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि यह देश की बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बेहद सख्त चेतावनी भी है। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि बैंकों की लापरवाही या उनकी उर्ध्वत सावधानी (ड्यू डिलिजेंस) में कमी के कारण कोई नागरिक ठगी का शिकार होता है, तो संबंधित बैंक को उस नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ का यह निर्देश इस मायने में क्रांतिकारी है क्योंकि यह पहली बार उपभोक्ताओं के नुकसान की सीधी जवाबदेही उन वित्तीय संस्थानों पर डालता है, जो सुरक्षा का दावा तो करते हैं लेकिन अपनी कमियों को छिपाने में लगे रहते हैं। अदालत द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आगामी संशोधित 'केवाईसी गाइडलाइंस' में पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान अनिवार्य रूप से शामिल करने का आदेश देना एक ऐसा नीतिगत बदलाव है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। इस आदेश के तहत आरबीआई को तीस नवंबर दो हजार छब्बिस तक नए नियम अधिसूचित करने हैं, जो इकतिसा दिसंबर दो हजार छब्बिस से देश भर में प्रभावी हो जाएंगे। अदालत का यह समयबद्ध दृष्टिकोण दर्शाता है कि न्यायपालिका इस संकट की गंभीरता को कितनी गहराई से महसूस कर रही है। इस पूरे संकट का सबसे स्याहल पल्लू यह है कि अब तक साइबर अपराध के मामलों में पूरी व्यवस्था तो दृष्टिकोण केवल पीड़ित को उपदेश देने या उसे जागरूक करने तक ही सीमित रहा है। सरकारों, पुलिस और बैंक अक्सर वित्तीय के माध्यम से यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि किसी को अपना ओटीपी या पासवर्ड न बताएं। परंतु, आज का साइबर अपराध केवल ओटीपी चोरी करने तक सीमित नहीं रह गया है। 'डिजिटल अरेस्ट' जैसी नई और परिष्कृत तकनीकों में अपराधियों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों का फजीरू भ्रम धरकर, पीड़ितों को मानसिक रूप से बंधक बना लिया जाता है और अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव में उनसे पैसे ऐंटे जाते हैं। ऐसे में साधारण नागरिक, चाहे वह कितना भी पढ़ा-लिखा क्यों न हो, भय और भ्रम के जाल में फंस जाता है।

साल देश में डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के कारण जानता है। लालभागा आठ सौ करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि गँवाई है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों की मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक तबाही और टूटे हुए सपनों की दस्तावेज़ है, जिन्होंने अपनी जमा-पूँजी को सुरक्षित मानकर बैंकों के हवाले कर दिया था। जब कोई अपराधी किसी खाते से करोड़ों रुपये ट्रान्सफर करने में सफल हो जाता है, तो यह केवल पीड़ित की सादगी नहीं, बल्कि उस बैंक के सुरक्षा चक्र की पूर्ण विफलता होती है। अदायतन से न इसी बिंदु पर प्रहार करते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि यदावत्



क्रिसी खाताधारक के सामान्य व्यवहार या पुराने पैटर्न से अलग कोई 'असामान्य ट्रांजेक्शन' या संदिग्ध लेनदेन होता है, तो बैंक को उस पर तुरंत अस्थाई रोक लगानी होगी। यह एक ऐसा सुरक्षात्मक कदम है जो अगर पहले से मुस्तेदी से लागू होता, तो आज आस सौ करोड़ रुपये का यह राष्ट्रीय नुकसान रोक जा सकता था। इस पर संगठित अपराध की रीढ़ की हड्डी 'म्यूल अकाउंट्स' यानी वे फर्जी बैंक खाते हैं, जिनका उपयोग साइबर उद्योग अपनी पहचान छिपाने और पैसे को अलग-अलग खातों में घुमाने लिए करते हैं। यह एक सर्वविरहित तथ्य है कि बिना बैंक के भीतर बैठे कुछ प्रष्ट तत्वों की मिलीभगत या फिर बैंकों के ढीले रखे के, हजारों की संख्या में फर्जी दस्तावेजों पर खाते खोला और उनमें करोड़ों का लेन-देन होना संभव नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन फर्जी खातों के जाल पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए साफ किया है कि बैंकों को अपने ग्राहक को जानो की प्रक्रिया को केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाना होगा। अब तब बैंक इन फर्जी खातों जरिए होने वाले अपराधों से खुद को अलग कर लेते थे और सारा दोष पुलिस या पीड़ित पर मढ़ दिया करते थे। लेकिन इस नए आदेश के बाद जब लापरवाही साबित होने पर मुआवजा देना बैंकों के लिए अपनी तान्त्री रूप से अनिवार्य हो जाएगा, तब वित्तीय संस्थाओं को अपनी ग्राहकों की सुरक्षा और अंतरिक निगरानी तंत्र को दुरुस्त करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब बैंकों को यह समझ आया कि सुरक्षा में चूक की कीमत उनके अपने मुनाफे से कटौती, तब वे संदिग्ध खातों पर नजर रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करने को तत्पर होंगे। इसके साथ ही, बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध डिजिटल अरेस्ट या वित्तीय धोखाधड़ी की गतिविधि की भनक लगते ही तुरंत नकदी नवदी की पुलिस स्टेशन को सूचित करें, जिससे वित्तीय सुरक्षा और संपन्न व्यवस्था के बीच एक मजबूत और त्वरित तालमेल स्थापित हो सके। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक आदेश जितना स्वागत योग्य है, इसे जमीन पर उतारने की राह में उतनी ही जटिल

नूतनित्यां भी खड़ी हैं। सबसे बड़ा कानूनी और व्यावहारिक संकट यह उठेगा कि 'बैंक की लापरवाही' और 'प्रादिक की गलती' के बीच की महीन रेखा को कौन और कैसे तय करेगा। बैंक निश्चित रूप से यह मामले में अपनी कानूनी टीमों के सहय सह साबित करने की पुरजोर कोशिश करेगी कि उपभोक्ता ने स्वयं अपनी संवेदनशील वित्तीय जानकारीयां या क्रेडेंशियल्स साझा किए थे, और इसलिए बैंक मुआवजे के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, बैंकिंग लॉबी की ओर इस बात को लेकर भी कानूनी प्रतिक्रिया देखाऊं तो मिल सकता है कि तकनीकी रूप से सुसुधित प्रणालियाँ तब तक युद्ध यदि कोई उपभोक्ता 'सोशल इंजीनियरिंग' या मनोवैज्ञानिक दबाव (जैसे डिजिटल अरेस्ट) का शिकार होता है, तो उसकी पूरी जानकारी देदादी बैंक पर कैसे थोपी जा सकती है। इसके लिए आरबीआई को अपने संशोधित नियमों में बहुत स्पष्ट, निष्पक्ष और पारदर्शी मापदंड तय करने होंगे ताकि पॉडित्तों को न्याय पाने के लिए बैंकों के चक्कर न काटने पड़ें और न ही उन्हें उपभोक्ता अदालतों के अंतहीन मुकदमों में उलझना पड़े। एक और चिंताजनक पहलू इस कानून के लागू होने की समयसीमा है। दिसंबर दो हज़ार छब्बिस तक का समय अपराधिक्य को नए रास्ते खोजने का मौका दे सकता है, इसलिए इस संक्रमण काल के दौरान भी बैंकों को अपनी सेख्हा से सुरक्षा मानकों को कड़ा करना चाहिए। निष्कर्षतः, सुप्रीम कोर्ट का यह कड़ा रुख देश के करोड़ों डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरी तरह साकार और सफल हो सकता है, जब देश का हर नागरिक डिजिटल रूप से खुद को सुरक्षित महसूस करे। अदालत ने अपना काम बखूबी कर दिया है और अब गंद पुरी तरह से रिजर्व बैंक और देश के तमाम वाणिज्यिक बैंकों के पाले में है। उन्हें यह समझना होगा कि वित्तीय सुरक्षा में संध केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी बैंकिंग व्यवस्था से जनता के भरोसे का उठ जाना है, और इस भरोसे को बनाए रखना अब उनकी कानूनी मजबूरी भी है।

होती माना जा सकता। बिहार के दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के निवर्तमान विधान परिषद सदस्य मदन मोहन झा को 324 मतों से हराया। इससे जन सुराज को विधान परिषद में पहली चुनावी सफलता मिली। पटना शिक्षक सीट पर राजने ने भाजपा के नवल किशोर यादव को हराया, जबकि सारण में निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज ने जीत दर्ज की। इन परिणामों से तीन बातें सामने आती हैं: एक, नए राजनीतिक विकल्प की गुंजाइश: जन सुराज ने सीमित लेकिन महत्वपूर्ण चुनावी सफलता हासिल की। दो, स्थानीय असंतोष का महत्व: पुराने और स्थापित उम्मीदवारों को भी मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। तीन, निर्दलीय उम्मीदवारों की प्रार्संगिकता: स्थानीय पहचान और मतदाताओं से सीधा संपर्क दलगत समर्थन के अतिरिक्त भी भूमिका निभा सकता है। जन सुराज के लिए असली चुनौती इस सफलता को दूसरे क्षेत्रों में भी संचालनात्मक विस्तार में बदलना होगी। महाराष्ट्र में महायुति और विपक्षी गठबंधन के बीच मुकाबला मिश्रित रहा। शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (एसपी) ने पुणे स्नातक और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की। वहीं भाजपा और महायुति के अन्य सहयोगियों को भी सफलता मिली। जबकि नागपुर स्नातक सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। यह परिणाम बताता है कि राज्य की राजनीति को केवल एक दल बनाम दूसरे दल के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। गठबंधन, स्थानीय उम्मीदवार, क्षेत्रीय नेतृत्व और मतदाता समूहों की प्राथमिकताएं भी परिणामों को प्रभावित करती हैं। विधान परिषद चुनावों में केवल निर्धारित शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के पात्र मतदाता मतदान करते हैं। इन चुनावों में मतपत्रों का इस्तेमाल होता है, ईवीएम का नहीं। इसलिए इन परिणामों से संचालनात्मक ताकत, स्थानीय असंतोष और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन पूरे राज्य या देश की जनता की राजनीतिक पसंद का सीधा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इससे बावजूद, परिणाम तीन व्यापक प्रश्न जरूर खड़े करते हैं: एक, क्या सत्तारूढ़ दल अपनी स्थानीय उपलब्धियों और संगठन को प्रभावी चुनावी समर्थन में बदल पा रहे हैं? दो, क्या विपक्षी दल स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवार और सारणीय तैयार कर पा रहे हैं? तीन, क्या नए राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवार स्थापित दलों के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनौती बन सकते हैं? वस्तुतः चार राज्यों के विधान परिषद चुनावों का सबसे बड़ा सियासी संदेश यह है कि भाजपा-राजग की समग्र बढ़त मिली है। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कायम है। उत्तर प्रदेश में लोक की सफलता, बिहार में जन सुराज का प्रवेश, कर्नाटक में कांग्रेस की हार और महाराष्ट्र में मिला-जुला परिणाम—ये सभी अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों को दर्शाते हैं। किसी एक राज्य की सफलता को दूसरे राज्य में दोहराया हुआ जनादेश मानना उचित नहीं होगा। अंततः राजनीतिक दलों के लिए इन चुनावों की उपयोगिता इसी में है कि वे मतदाताओं के संदेश को समझें, संचालनात्मक कमियों की पहचान करें और जनता के मुहों पर अपनी जवाबदेही बढाएं।

विचार

एक सूरज का अस्त, जिसकी
रोशनी से रोशन हुए अनेक दीये!

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

आज की सुबह कुछ अलग है। बिहार की धरती पर एक भारी-सी चुपनी है और देश के उन लाखों घरों में, जहाँ रात को रोशनी जलती थी, आज एक अजीब से खालीपन की अनुभूति है। 30 अक्टूबर 2026 को वह सूरज अस्त हो गया, जिसकी रोशनी से अनगिनत दीये जले और निरंतर प्रकाशित हैं। डॉ. रविन्द्र किशोर सिन्हा (आरके सिन्हा) 75 वर्ष की आयु में पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली/नोएडा स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे, फिर उनका शरीर थक गया था... उनकी इच्छाशक्ति और सपने नहीं! वे बिहार के विक्रुत भाजपा नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य और विश्व प्रसिद्ध सुरक्षा कंपनी सिक्योरिटी एंड इंटीलजेंस सर्विसेज (एसआईएस) के संस्थापक थे। उनका जन्म उस पूरे स्वर्णिम अध्याय का अंत है, जिसने संघर्ष को अपना धर्म बनाया और देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े करोड़ों लोगों के हाथों में रोजगार की लाठी थमाई। आरके सिन्हा के जीवन को देखें तो ध्यान में आता है, उनका पूरा जीवन एक ऐसे दैदीप्यमान सूरज की तरह रहा, जो खुद तपकर और संघर्षों की भट्टी में गलकर, दूसरों की जिंदगी में उम्मीदों के अनगिनत दीये जलाता है। आज जब वे अस्ताचल की ओर चले गए हैं, तो लगता है जैसे कोई बड़ा दिया बुझ गया हो...। आरके सिन्हा के जीवन का सबसे मजबूत और प्रेरक स्तंभ पत्रकारिता रहा। सतर के दशक में एक आम रिपोर्टर के रूप में कलम उठाते वला इस इंसान ने आगे चलकर देश की सबसे पुरानी बहुभाषी समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अध्यक्ष (चेयरमैन) के रूप में इसकी कमान संभाली। उन्होंने इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार एजेंसी को सिर्फ व्यावसायिक ऊंचाई नहीं दी, बल्कि उसे देशहित और राष्ट्रीय चेतना के प्रति समर्पित रखने का संकल्प भी निभाया। उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखने के साथ ही यह देश की नब्ब को समझना और उसे सही दिशा देना था। जब वे हिन्दुस्थान समाचार के अध्यक्ष थे, तो उनका आवाज में एक अलग ही वजन था। वे जानते थे कि शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। उनकी कलम ने कभी समझौता नहीं किया और यही वजह थी कि देश के बौद्धिक और मीडिया जगत में उन्हें एक संरक्षक के रूप में देखा जाता रह। आज जब वे नहीं रहे, तो लगता है जैसे पत्रकारिता के उस स्वर्णिम दौर की एक आखिरी कड़ी भी टूट गई हो। रविन्द्र किशोर सिन्हा का जन्म 22 सितंबर 1951 को बिहार के बक्सर (भोजपुर जिला) के बहियारा गांव के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनकी आंखों में कुछ अलग करने की चाह थी।

प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। परिवार की माली हालत और तत्कालीन बिहार की आर्थिक परिस्थितियाँ युवाओं को संघर्षों की गहरी खाई में धकेलने के लिए पर्याप्त थीं पर आरके सिन्हा की आंखों में जो सपने थे, उन्हें किसी भी रूप में सीमित नहीं किया जा सकता था। वे जानते थे कि यदि रास्ते खुद नहीं बनते, तो उन्हें अपनी इच्छाशक्ति के हथौड़े से तोड़कर बनाना पड़ता है। शुरुआती दौर में उन्होंने एक प्रशिक्षण पत्रकार (ट्रेनी रिपोर्टर) के रूप में करियर की शुरुआत की, जहाँ उनका मासिक वेतन महज 230 रुपये था। एक खोजी पत्रकार के तौर पर उन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी खास पहचान बना ली। सन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने खुलना-कुष्टिया-ईशुरदी सेक्टर में एकमात्र युद्ध संवाददाता के रूप में जांबाज रिपोर्टिंग की। मोर्चे पर जाकर गोलियों की गूँज और भारतीय सेना के पराक्रम को अपनी कलम से पन्नों पर उतारना उनके जीवन का एक ऐसा अनुभव था, जिसने उनकी नियति को पूरी तरह बदल दिया। उस समय उनके भीतर देशभक्ति और सैनिकों के प्रति गहरा सम्मान घर कर गया था। वे अक्सर कहते थे कि युद्ध के मैदान से लौटे जवानों की आंखों में जो दर्द देखा, वह उन्हें रात भर सोने नहीं देता था। पत्रकारिता के दिनों में ही आरके सिन्हा ने उन पूर्व सैनिकों के दर्द को बहुत करीब से देखा, जो देश के लिए लड़कर आए थे, किंतु सेवानिवृत्ति या चोटिल होने के बाद समाज में आजीविका के लिए दर-दर भटकने को मजबूर दिखे। इसी दौरान बिहार की धरती पर संपूर्ण क्रांति के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण (जेपी) का आंदोलन अंगड़ाई ले रहा था। आरके सिन्हा छत्र आंदोलन और जेपी के विचारों से गहराई से जुड़े थे, जिसके कारण उन्हें: अतः अपनी पत्रकारिता की नौकरी भी गंवानी पड़ी। यह जेपी आंदोलन का ही दौर था जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सिन्हा के भीतर छिपे समाजिक सरोकारों को भांपते हुए उन्हें एक अमूल्य सुझाव दिया। जेपी ने कहा कि देश के लिए मर-मिटने वाले इन सेवानिवृत्त सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को समाज में पुनर्स्थापित करने और उनके हुरार का सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए।

एक नजर

किसान मेला–सह–प्रदर्शनी का आयोजन, किसानों को मिली आधुनिक खेती के गुर



नवादा,एजेंसी। कृषि विभाग, नवादा के तत्वावधान में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकरण (आत्मा), नवादा द्वारा आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला-सह-प्रदर्शनी का शुभारंभ शुक्रवार को जिला कृषि पदाधिकारी –सह-परियोजना निदेशक, आत्मा अजीत प्रकाश ने किया। मेले में कुल के सभी 14 प्रखंडों के प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। किसानों द्वारा उन्नत कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि एवं संबद्ध विभागों के स्टॉल के माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदान तथा आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक रविकांत चौबे एवं श्री अगंद कुमार ने किसानों को रबी फसलों की उन्नत खेती, कीट-व्याधि प्रबंधन तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। सिरदला प्रखंड के युवा किसान श्री अनुराग कुमार ने फसल विविधीकरण के अंगतर्म समेकित कृषि प्रणाली एवं मल्टीलेयर फार्मिंग की जानकारी दी। वहीं, रोह प्रखंड के युवा किसान श्री गुरु सरंग ने बकरी पालन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारी कार्यों एवं अपने अनुभवों को साझा किया। मेले के प्रथम दिन जिले के आठ प्रखंडों से आए किसानों ने भाग लिया तथा कृषि वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों से कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम में कृषि अभियंत्रण, उद्यान, भूमि संरक्षण, बीज उत्पादन एवं विपणन, प्रक्षेत्र, बीज विश्लेषण तथा मिट्टी जांच सहित कृषि विभाग के विभिन्न पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं किसान सलाहकार उपस्थित रहे।

सारण में 30-36 घंटे की विसर्जन शोभायात्रा के बाद हनुमान जी की विदाई, प्रशासन ने ली राहत की सांस

सारण। जिले के ऐतिहासिक रविलगंज प्रखंड में भगवान हनुमान जी के ननिहाल से जुड़ी अनोखी और पारंपरिक मूर्ति विसर्जन शोभायात्रा का समापन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। लगभग 30 से 36 घंटे तक अनवरत चली इस विसर्जन शोभायात्रा में भगवान विष्णु जी अपने ननिहाल के श्रद्धालुओं के घर घर पहुंचकर मिलन किया और श्रद्धालु भी अपनी श्रद्धा, भक्ति और समर्थ के अनुसार मेवा मिष्ठान और विभिन्न प्रकार की मालाओं से उनका स्वागत सत्कार आरती के उपरांत अगले वर्ष पुन: आने की प्रार्थना कर अपने आराध्य भगवान हनुमान जी, भगिना बजरंगबली माता अंजनी के पुत्र, बड़े सरकार का विदाई किया। इस दौरान चक्रवाती तूफान के असर से राज्यभर में हो रही लगातार बारिश और ठंडी हवाओं के बीच भी युवाओं का उत्साह और जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ। वर्षा से प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अखाड़ा समिति द्वारा बड़े-बड़े त्रिपाल और पॉलिथीन शीट्स का विशेष उपयोग किया गया, जिससे विसर्जन शोभायात्रा अपने निर्धारित रूट पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ती रही। इस महाआयोजन में सारण के अलावा बिहार के अन्य जिलों और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस यात्रा में विभिन्न समितियों के सदस्यों ने अपने पारंपरिक युद्ध कौशल और कलात्मक प्रदर्शन से सबको अर्चभित कर दिया। भगवान हनुमान का ननिहाल होने के कारण इस क्षेत्र की धार्मिक महत्ता अत्यंत विशिष्ट है। दो दिनों तक चले इस वृहद आयोजन के सकुशल संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

60 हजार का लोन दिलाने के नाम पर सैकड़ों महिलाओं से लाखों की ठगी



किशनगंज। फर्जी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाकर लोन देने के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले अंतरजिला गिरोह का किशनगंज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना राजू कुमार को एसटीएफ एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को अपने साथ के 50 हजार रुपये नकद, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। शुक्रवार को पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरोह ने फिनसपोर्ट माइक्रो फाउंडेशन के नाम पर सीमांचल क्षेत्र में ठगी का नेटवर्क फैला रखा था। मामले का खुलासा तब हुआ, जब ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के भिमवालीस चौक वार्ड संख्या-4 निवासी लक्ष्मी देवी ने 8 मई 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई िशकायत के अनुसार, कंपनी के एजेंट गांवों में पहुंचकर चार-चार महिलाओं का समूह बनाकर प्रत्येक सदस्य को 60 हजार रुपये का लोन दिलाने का झांसा देते थे।

इसके लिए लोन कार्ड बनवाने और घरेलू उपयोग के सामान खरीदने के नाम पर प्रत्येक महिला से चार से सात हजार रुपये जमा कराए गए। 4 मई को जिलेबिया मोड़ स्थित कंपनी के कार्यालय में करीब 200 महिलाओं से रुपये वसूले गए। 8 मई को सामान घर पहुंचाने और लोन देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर कार्यालय में ताला लटका मिला और सभी कर्मचारी फरार हो गए। इस संबंध में ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 148/26 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। एसपी संतोष कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला आसूचना इकाई को तकनीकी एवं मानवीय सूचना जुटाने का निर्देश दिया। जांच में फिनसपोर्ट माइक्रो फाउंडेशन फर्जी कंपनी पाई गई। इसके बाद एसडीओ-2 मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की मदद से वैशाली में छापेमारी कर राजू कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने गिरोह में बिहार के कई जिलों के दर्जनों लोगों के शामिल होने की जानकारी दी।

भाजपा से राज्यसभा के पूर्व सदस्य और उद्योगपति रवीन्द्र किशोर सिन्हा का निधन, एसआईएस समूह के संस्थापक थे

पटना,एजेंसी। उद्योगपति और भाजपा के वरिष्ठ नेता रवीन्द्र किशोर सिन्हा का शुक्रवार को नोएडा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। बिहार में भोजपुर जिले के बहियारा गांव निवासी रविन्द्र किशोर सिन्हा का जन्म 22 सितम्बर 1951 को हुआ था। पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता आर के सिन्हा ने नोएडा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और कारोबारी जगत में शोक की लहर है। डॉ आरके सिन्हा एसआईएस समूह के संस्थापक और चेयरमैन थे। राजनीति के साथ-साथ उद्योग जगत में उनकी विशिष्ट पहचान थी। भाजपा के शुरुआती दौर से जुड़े रहे डॉ सिन्हा ने पार्टी और संगठन के लिए लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह राज्यसभा सांसद के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। स्व आरके सिन्हा के निजी सहायक सतीश राजू और मनीष किशोर ने हिन्दुस्थान समाचार से बातचीत में कहा कि बीते वर्ष से ही उनकी हालात नाजुक थी। उनका इलाज सिंगापुर से चल रहा था। आज सुबह यह दुख:द समाचार हमलोगों को प्राप्त हुआ है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली से पटना लाया जाएगा। पटना के पाटलिपुत्र स्थित अटनपूर्णा भवन में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि पार्थिव शरीर को कब लाया जायेगा।

भाजपा के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा के निधन के बाद भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संजीव चौरसिया ने एक्स पर लिखा, 'जनसंघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य आरके सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। उनके जाने से

कटिहार में पत्रकार का अपहरण कर मांगी 10 लाख रुपये फिरौती, पुलिस ने 6 घंटे में सकुशल छुड़ाया, 3 गिरफ्तार

कटिहार। खाद की कालाबाजारी से जुड़ी खबर को लेकर एक पत्रकार का अपहरण कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले का कटिहार पुलिस ने महज छह घंटे में सफल उद्देदन कर लिया है। पुलिस की विशेष जांच टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहृत को सकुशल बरामद करने के साथ ही घटना में शामिल तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही वारदात में प्रयुक्त काले रंग की किआ कार और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है।

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आजमनगर थाना क्षेत्र के इमाम नगर निवासी वादी गुलाम मुर्तजा ने रोशना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर को वे अपने पत्रकार साथी मो. कलीम के साथ समाचार संकलन के लिए प्राणपुर जा रहे थे। इसी दौरान खाद की कालाबाजारी से संबंधित समाचार प्रकाशित करने को लेकर मो0 आशिक द्वारा उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके कुछ ही देर बाद लाभा जीरो माइल के आगे काले रंग की किआ कार से पीछा कर हथियार के बल पर उनका

जबरन अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता पीड़ित को मारपीट करते हुए मनिहारी के रास्ते अमदाबाद ले गए, जहां उनकी रिहाई के बदले परिजनों से 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। राशि नहीं मिलने पर उन्हें दियारा इलाके में ले जाकर हत्या करने की साजिश रची जा रही थी। इस संबंध में रोशना थाना कांड संख्या 205/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-1) के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम (एसआईटी) का गठन किया गया। टीम ने वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर जाल बिछाते हुए छह घंटे के भीतर अपहृत को सकुशल मुक्त कराला लिया। मौके से पुलिस ने मनिहारी थाना क्षेत्र के सोझाईगंी निवासी मो. आशिक (37 वर्ष), मो. साबिर आलम (21 वर्ष) तथा बोरनी निवासी मनीष कुमार गोस्वामी (21 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन व मोबाइल बरामद कर आरोपियों के खिलाफ अग्रतर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरवार शाम करीब सात बजे विनय विश्वास स्वयं फॉर्च्यूनर चलाकर अपने पैतृक गांव से पूर्णिया के प्रभात कॉलोनी स्थित आवास लौट रहे थे। इसी दौरान कसान पुल पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर गयी। हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर एकर हो गए। सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिनव पाराशर, सदर एसडीएम विग्नेश टी. ए., ट्रैफिक डीएसपी तथा सदर थाना पुलिस सहित पुलिस बल के जवान मौके पर पहुंचे। बचाव अभियान शुरू किया गया और काफी मशकत के बाद करी की सहायता से वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। इस दौरान करीब एक घंटे तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। विनय विश्वास को तत्काल राजकीय

राष्ट्रीय समाचार

भाजपा से राज्यसभा के पूर्व सदस्य और उद्योगपति रवीन्द्र किशोर सिन्हा का निधन, एसआईएस समूह के संस्थापक थे



सामाजिक और राजनीतिक जगत को बड़ी क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दें।

पत्रकारिता से की थी करियर की शुरुआत

स्व. आरके सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। राजनीति विज्ञान

भागलपुर में अर्णब तूफान का कहर: खेतों में गिरी धान की तैयार फसल, किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी

भागलपुर,एजेंसी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान ‘अर्णब’ का असर भागलपुर जिले में साफ तौर पर दिखने लगा है। पिछले दो दिनों से हो रही रुक-रुक कर बारिश और तेज हवाओं के कारण जिले के विभिन्न प्रखंडों में धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है।

खेतों में पककर तैयार खड़ी धान की फसलें तेज हवा के झोंकों से जमीन पर गिर गई हैं, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। इस साल बेहतर मौंसून के कारण किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त पर आए इस प्राकृतिक संकट ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल, जिले के अधिकांश हिस्सों में धान की फसल इस समय पूरी तरह तैयार हो चुकी है और कई जगहों पर कटनी की तैयारियां चल रही थीं। बारिश और तेज हवा के कारण फसल के खेतों में सो जाने से बालियों से दाने झड़ने का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा, खेतों में जलजमाव होने से गिरी हुई फसलों में नमी बढ़ेगी, जिससे अनाज की गुणवत्ता खराब होने और सड़ने की आशंका बढ़ गई है। जगदीशपुर के किसान राजकुमार पंजियारा का कहना है कि साल भर खून-पसीना बहाकर फसल तैयार की थी। इस बार पैदावार बहुत अच्छी थी। सोचा था दिवाली पर फसल बेचकर कर्ज चुकाएंगे, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अब न तो खाने को अनाज बचेगा और न ही महाजन का कर्ज लौटाने का कोई रास्ता दिख रहा है। सरकार को तुरंत नुकसान का सर्वे करारक मुआवजा देना चाहिए। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है

कि यह मौसम धान की कटाई का है। ऐसे में जिन किसानों ने फसल काट ली है, वे उसे तुरंत सुरक्षित और सूखे स्थानों पर रखें। खुले में रखे अनाज को तिरपाल से ढकें। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लें ताकि नमी के कारण फंगस न लगे। खेतों में जलजमाव होने पर पानी निकालने का तुरंत प्रबंध करें। चक्रवात के कारण हुए इस औंचक नुकसान से परेशान

विधान परिषद चुनाव में दरभंगा से एनडीए दोनो उम्मीदवार की हार पर मंथन जारी

मधुबनी। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के दोनो प्रत्यक्षियों की हार पर मंथन विमर्श जारी है।एनडीए कार्यकर्त्ता मर्मांत हैं। शुक्रवार को एनडीए के घटक दल से जुड़े लोगों ने दरभंगा क्षेत्र से करारी हार की मुहताज होने का कारण शीघ्र नेतृत्व की कथित अकर्मण्यता बताया। राष्ट्रीय जनता दल व जन सुरज के प्रत्यशी की यहां जीत हुई है। एनडीए प्रत्यशी की हार को लोग मंथन के लिए शुक्रवर को आरोप प्रत्यरोप लगाया है। बताया की जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के गृह क्षेत्र में दोनों प्रत्यशी की हार एनडीए घटक दल के लोगों को शर्मनाक स्थिति में ला दिया है। कारण दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर व जदयू प्रत्यशी को महज 823 वोट प्राप्त हुए। जबकि भाजपा के उम्मीदवार सर्वेश कुमार दुसरे नंबर पर रहे हैं। ब्ताया की बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री भाजपा सांसद गिरिराज सिंह की दवंग वचंस्व है।समस्तीपुर में लोजपा सांसद शांभवी हैं।भाजपा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय का दबदबा वहां है। दरभंगा में भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर मधुबनी में भाजपा सांसद अशोक यादव व झंझारपुर में जदयू सांसद रामप्रीत मंडल कद्दावर नेता हैं। बावजुद दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के दोनो प्रत्यशी की करारी हार हुई है। जो समर्नाक है। खासकर राज जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के गृह क्षेत्र में दोनों उम्मीदवारों का हार जाना उनके सेहत व प्रतिष्ठा पर सर्वालिया निशान लगाया है। बताया कि समस्तीपुर में उप मुख्य मंत्री विजय चौधरी भी कारगर सहयोग नहीं किया। इधर राष्ट्रीय लोक समता के मधुबनी नगर विधायक माधव आनंद मधुबनी में विराजमान रहते कोई सहयोग नहीं कर पाए। जबकि नीतिश मिश्रा झंझारपुर में यूथ आईकोन विधायक सहित काबीना मंत्री के रूप में अभी स्थापित हैं। इसी प्रकार अरुण शंकर प्रसाद खाजौली क्षेत्र से जीतकर राज्य सरकार में काबीना मंत्री बने हुए हैं। भाजपा के दो- दो मंत्री मिथिलांचल से हैं। बावजुद इन लोगों का कोई खास पहल नहीं रहा। मधुबनी जिला के प्रभारी मंत्री के रूप में लेसी सिंह भी कारगर साबित नहीं रहें।



कि यह मौसम धान की कटाई का है। ऐसे में जिन किसानों ने फसल काट ली है, वे उसे तुरंत सुरक्षित और सूखे स्थानों पर रखें। खुले में रखे अनाज को तिरपाल से ढकें। भंडारण से पहले दानों को अच्छी तरह सुखा लें ताकि नमी के कारण फंगस न लगे। खेतों में जलजमाव होने पर पानी निकालने का तुरंत प्रबंध करें। चक्रवात के कारण हुए इस औंचक नुकसान से परेशान

किसान अब सरकार और जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि बीज, खाद और जुताई के लिए उन्होंने बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लिया था। अगर सरकार ने जल्द ही फसलों के नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता नहीं दी, तो उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।

मुआवजा मुगतान के बाद मोलानाथ पलाईओवर के काम ने पकड़ी रफ्तार, 41 में से 37 पिलर बनकर तैयार

भागलपुर। शहर के लोगों को महाजाम से मुक्ति दिलाने वाले बहुप्रतीक्षित भोलानाथ पुल ओवरब्रिज और फलाईओवर निर्माण को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। परियोजना की राह में लंबे समय से रोड़ा बनी मिरजानहाट शौतला स्थान चौक के पास भूमि अधिग्रहण कला सम्मन्य के समाधान हो गया है। भू-अर्जन के लिए 15 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान कर चुका है। इसके साथ ही 33 पिलरों का आपस में जोड़ने का काम भी मुकम्मल हो गया है। आंकड़ों के अनुसार, फाउंडेशन का कार्य 96% से 98%, सब-स्ट्रक्चर का 76% से 87%, और सुपर-स्ट्रक्चर का लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना की देरी और वर्तमान अड़चनों को लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के मुख्य अभियंता ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि ‘मिरजानहाट में मुआवजा भुगतान के बाद

काम में तेजी आई है। रेलवे ट्रैक के ऊपर गर्डर लॉन्चिंग और इशाकचक पिलर निर्माण के लिए पूर्व रेलवे के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण किया गया है। रेलवे सुरक्षा मानकों के तहत, गर्डर लॉन्चिंग और पिलर ढलाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक लेना अनिवार्य है, जिसकी तकनीकी अनुमति प्रक्रियाधीन है। जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए हमने काम की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया है और हमारी कोशिश 30 जून 2027 की नई आधिकारिक डेडलाइन के भीतर परियोजना को पूर्ण करने की है। काम में तेजी आने के बावजूद भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक के आगे और बौसी रेलवे पुल संख्या-2 पर बन रहे आरओबी के मिरजानहाट वाले हिस्से में जमीन हस्तांतरण का पेंच फंसा हुआ है। मुख्य अभियंता के अनुसार, त्रिमूर्ति चौक के पास भू-अर्जन के लिए 39 करोड़ का मुआवजा जल्द बांटे जाने की तैयारी चल चुका है। जिसके साथ ही 33 पिलरों और स्थानीय दुकानदारों से लगातार वार्ता जारी है ताकि किसी प्रकार का गतिरोध न हो। इसके साथ ही, रेलवे यार्ड का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू न होने के कारण गंदा पानी सीधे पुल के नीचे गिर रहा है, जिससे लिए रेतयों और स्थानीय बाधा आ रही है। नगर निगम और रेलवे के बीच इसे लेकर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जलजमाव की समस्या पर काबू पाया जा सके।

एक नजर

हायलो ओपनः सिंधु और अनमोल खरब त्वाटर् फाइनल में



सारबूकेन,एजेंसी। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने हायलो ओपन 2026 के महिला एकल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। गुरुवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने फ्रांस की रोसी ओक्टाविया पंकासारी को सीधे गेम्‌ों में 21–९, 21–6 से हराया। यह मुकाबला 30 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना डेनमार्क की अमाली शुल्ज से होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु इस सुपर 500 प्रतियोगिता में फ्रेंच ओपन सुपर 750 में उपविजेता रहने के बाद उतरी हैं। फ्रेंच ओपन के फाइनल में उन्हें विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन से यंग से हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच युवा भारतीय खिलाड़ी अनमोल खरब ने भी शानदार वापसी करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। 19 वर्षीय अनमोल ने प्री-क्वार्टर फाइनल में उच्च वरीयता प्राप्त डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन को एक घंटे तीन मिनट तक चले मुकाबले में 11–21, 21–18, 25–23 से हराया। पहला गेम गंवाने के बाद अनमोल ने दूसरे गेम में वापसी की और मुकाबले को निर्णायक गेम तक पहुंचाया। तीसरे गेम में उन्होंने धैर्य बनाए रखते हुए 25–23 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अब उनका सामना भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। हालांकि, मालविका बंसोड़ को महिला एकल के प्री-क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कनाडा की वेन यू झांग ने 21–11, 21–17 से हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया।

विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप दिसंबर में, इस्तांबुल करेगा मेजबानी

नई दिल्ली। तुर्किये का इस्तांबुल शहर दिसंबर 2026 में फिडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। साल के अंतिम सप्ताह में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में दुनिया के कई शीर्ष शतरंज खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। फ्रीडम होलिंग्स कॉर्प को इन चैंपियनशिप का शीर्ष प्रायोजक बनाया गया है। यह कंपनी 2023 से अंतरराष्ट्रीय शतरंज महाश्व (फिडे) की रणनीतिक साझेदार है। यह प्रायोजन वर्ष 2026 के लिए हुए व्यापक सहयोग समझौते का हिस्सा है। इसके तहत फ्रीडम होलिंग्स कॉर्प कैडिडेट्स टूर्नामेंट और विश्व चैंपियनशिप मुकाबले सहित फिडे के प्रमुख आयोजनों में सहयोग करेगी। इसके अलावा जमीनी स्तर पर शतरंज को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र, स्कूल कार्यक्रम और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पहचान से जुड़ी योजनाओं में भी मदद करेगी। फिडे के अध्यक्ष तिमूर तुरलोव ने इस्तांबुल को मेजबानी सौंपे जाने पर खुशी जताई। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा कि तुर्किये ने बड़े अंतरराष्ट्रीय शतरंज आयोजनों की मेजबानी में अपनी क्षमता साबित की है और खेल के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस्तांबुल इससे पहले 2012 में 40वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा 2025 में शहर में विश्व युवा ब्लिट्ज और रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का भी सफल आयोजन हुआ था। तुरलोव ने कहा कि विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप को इस्तांबुल लाना खुशी की बात है। तुर्किये ने बार–बार विश्वस्तरीय शतरंज प्रतियोगिताओं के आयोजन की अपनी क्षमता दिखाई है और खेल को हर स्तर पर आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये चैंपियनशिप परंपरागत रूप से हर साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित होती हैं। इस बार मुकाबले 25 से 30 दिसंबर तक खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में दुनिया भर के सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और ओपन तथा महिला वर्ग में रैपिड और ब्लिट्ज की कुल चार विश्व चैंपियनशिप के खिताब दांव पर होंगे। मौजूदा चैंपियनों में विश्व के शीर्ष रेटिंग वाले खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन शामिल हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते थे। महिला रैपिड वर्ग की मौजूदा चैंपियन एलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना हैं, जबकि महिला ब्लिट्ज का खिताब बिबिसारा असाउबायेवा के पास है।

चोट से उबर रहे नीरज चोपड़ा, अगले कुछ सप्ताह में फिर शुरू करेंगे अभ्यास और पुनर्वास

नई दिल्ली। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट से तेजी से उबर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी चोट में काफी सुधार हुआ है और वह अगले कुछ सप्ताह में अभ्यास तथा पुनर्वास की प्रक्रिया दोबारा शुरू करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की मीडिया टीम से बातचीत में नीरज ने अपनी चोट के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ' अब मेरी चोट काफी बेहतर है। शुरुआत में पहले डेढ़ महीने के दौरान मुझे कुछ परेशानियां हुई थीं लेकिन अब काफी सुधार हुआ है। मैंने डॉ. दिनशां पारदीवाला से परामर्श लिया है। उन्होंने मुझे अभ्यास दोबारा शुरू करने और उचित पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी है। मेरी योजना अगले कुछ सप्ताह में दोनों शुरू करने की है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने चिकित्सकों की सलाह के अनुसार पूरी तरह आराम किया। उन्होंने कहा, 'मेरी चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी थी और मैंने उसका पूरी तरह पालन किया। प्रतियोगिताओं के मामले में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) और भारतीय खेल प्राधिकरण कई वर्षों से मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं लंबे समय से टॉप्स के कोर समूह का हिस्सा हूं और जब भी मुझे किसी तरह की मदद की जरूरत होती है, वे मेरे साथ खड़े रहते हैं। नीरज ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से खेलो इंडिया खेल उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दिए जाने का भी स्वागत किया। उन्होंने इसे भारतीय खेलों के लिए बड़ा कदम बताया। नीरज ने कहा, 'यह शानदार पहल है। खिलाड़ियों को भारत में कुछ खास खेल उपकरण खरीदने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर उन्हें विदेश से उपकरण मंगाने पड़ते हैं। ऐसी योजनाओं से जब उपकरणों का निर्माण भारत में ही होगा, तो खिलाड़ियों के लिए उन्हें हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। उन्होंने आगामी युवा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दीं। नीरज ने कहा, 'युवा ओलंपिक में जाने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। इस अनुभव का आनंद लें और बहुत ज्यादा दबाव न लें या घबराएं नहीं। वहां मिलने वाला दबाव आपके लिए अच्छा है क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस अवसर का उपयोग दूसरे खिलाड़ियों को देखने और दबाव को अपनी ताकत बनाने के लिए करें। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। '

हरमनप्रीत और सुखजीत के दो-दो गोल से भारत ने चीन को 5-2 से हराया

जालंधर,एजेंसी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब–2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए गुरुवार को चीन को 5–2 से हरा दिया। ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और ज्येयर ऑफ द मैच सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल दागा। इस जीत के साथ गत चैंपियन भारत ने दो मैचों में छह अंक हासिल कर अंक तालिका में शीर्ष स्थान बनाए रख। भारत की ओर से सुखजीत ने 12वें और 34वें मिनट में गोल किए। हरमनप्रीत ने 27वें और 31वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदला, जबकि जुगराज ने 47वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से गोल किया। चीन की ओर से यांग पेंग ने 26वें और चेन चोंगचोंग ने 36वें मिनट में गोल किए।

भारत ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन चीन ने मजबूत रक्षात्मक रणनीति के दम पर मेजबान टीम को आसानी से मौके नहीं बनाने दिए। 12वें मिनट में जुगराज के लंबे हवाई पास को नियंत्रित करने के बाद सुखजीत ने आगे बढ़ते गोलकीपर के ऊपर से गेंद उठाकर शानदार गोल किया। चीन ने 14वें मिनट में बराबरी का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर सूरज कंकेरा ने लगातार दो बचाव कर बढ़त कायम रखी। दूसरे क्वार्टर में चीन ने 26वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर से गोल कर स्कोर 1–1 कर दिया। हालांकि, भारत ने तुरंत जवाब दिया और अगले ही मिनट हरमनप्रीत ने अपनी दमदार ड्रैग–फिलक से टीम को फिर बढ़त दिला दी। हाफ-टाइम तक भारत 2–1 से

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए प्रसिद्ध कृष्णा, भारत ए टीम से जुड़ेंगे

नई दिल्ली। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा हैमस्ट्रिंग की चोट से समय पर उबरने में नाकाम रहने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। अब वह न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए भारत ए टीम से जुड़ेंगे। हालांकि, इससे लिए उन्हें फिटनेस जांच और मैदान पर वापसी से जुड़ा आकलन (आरटीपी) पास करना होगा। इसके बाद ही उनके खेलने पर फैसला होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बयान में कहा कि प्रसिद्ध को मैच खेलने के लिए जरूरी गेंदबाजी कार्यभार हासिल करने में अभी अतिरिक्त समय लेगेगा। वनडे टीम में उनकी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पहले ही आराम दिया जा चुका है। इस बीच, ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी अब पूरी वनडे श्रृंखला के बजाय केवल पहले मुकाबले में खेलेंगे। इसके बाद वह छह नवंबर से शुरू होने वाले न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट के लिए भारत ए टीम से जुड़ेंगे। यह फैसला 19 नवंबर से वेल्सिंग्टन में शुरू होने वाली पहली टेस्ट श्रृंखला से पहले नीतीशा को लाल गेंद से खेलने का

विथना ओपन के त्वाटर् फाइनल में पहुंचे ज्वेरेव, पहली बार विश्व नंबर एक बनना सुनिश्चित

विथना,एजेंसी। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने विथना ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के साथ ही पहली बार विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना सुनिश्चित कर लिया है। गुरुवार को खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल में ज्वेरेव ने नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर को 6–4, 7–5 से हराया। सोमवार को जारी होने वाली नई रैंकिंग में वह इटली के यानिक सिनर को पीछे छोड़कर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बन जाएंगे। 29 वर्षीय ज्वेरेव फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन के खिताब जीतने के बाद शानदार लय में हैं।

वह 1991 में बोरिस बेकर के बाद विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले जर्मनी के दूसरे पुरुष टेनिस खिलाड़ी होंगे। वर्ष 1973 में विश्व रैंकिंग शुरू होने के बाद शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले वह 30वें पुरुष खिलाड़ी बनेंगे। ग्रिक्सपुर के खिलाफ ज्वेरेव ने दमदार खेल दिखाया। उन्होंने लगातार दो सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। मैच का अंत उन्होंने इस लगाकर किया। इस उपलब्धि के बाद कोर्ट पर विशेष समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उनकी टीम के साथ ऑस्ट्रिया के पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी थॉमस मस्टरथ भी मौजूद रहे। ज्वेरेव ने कहा कि दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने का एहसास बेहद खास है। किसी टूर्नामेंट का खिताब जीतने से यह उपलब्धि अलग है। उन्होंने कहा कि नई रैंकिंग जारी होने पर अपने नाम के आगे



आगे था। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने 31वें मिनट में एक और पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त 3–1 कर दी। इसके तीन मिनट बाद सुखजीत ने अपना दूसरा गोल दागा। आदित्य अर्जुन लालगे ने कप्तान के हवाई पास को नियंत्रित कर गेंद सुखजीत की ओर बढ़ाई, जिसे उन्होंने गोल में पहुंचा दिया। चीन ने 36वें मिनट में चेन चोंगचोंग के पेनाल्टी कॉर्नर

मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव, उथप्पा और टी. दिलीप को मिली अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली,एजेंसी। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र से पहले मुंबई इंडियंस ने अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव किया है। नए मुख्य कोच कीरोन पोलार्ड के नेतृत्व में टीम ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को बल्लेबाजी कोच और टी. दिलीप को क्षेत्ररक्षण कोच नियुक्त किया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल मैक्लेनाघन को गेंदबाजी कोच और धवल कुलकर्णी को विकासात्मक गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुंबई इंडियंस ने इससे पहले लसिथ मलिंगा, पारस म्हाम्ब्रे और कार्ल हॉर्पकिन्सन से नाता तोड़ लिया था। मलिंगा 2024 से टीम के गेंदबाजी कोच थे, जबकि हॉर्पकिन्सन क्षेत्ररक्षण कोच की भूमिका निभा रहे थे।

रॉबिन उथप्पा पहली बार किसी आईपीएल टीम के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बने हैं। उन्होंने 2022 सत्र के बाद आईपीएल से संन्यास ले लिया था। उथप्पा 2008 में आईपीएल के पहले सत्र में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे और नियमित रूप से अंतिम एकादश में खेलते थे। बाद में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ जहीर खान के बदले हुए शुरुआती ट्रेड में शामिल किया गया था। मिशेल मैक्लेनाघन मुंबई इंडियंस के तीन खिताबी अभियानों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। न्यूजीलैंड के इस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 2015, 2017 और 2019 में टीम की खिताबी जीत के दौरान 56 मुकाबलों में 71 विकेट लिए थे। वह 2020 में खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली टीम का भी हिस्सा थे, हालांकि उन्हें उस सत्र में खेलने का मौका नहीं मिला। वह



2024 में आईएलटी20 में मुंबई इंडियंस एमिरेट्स के गेंदबाजी कोच भी रहे थे। उनकी देखरेख में टीम ने खिताब जीता था। टी. दिलीप भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के क्षेत्ररक्षण कोच के रूप में पहचान बना चुके हैं। वह भारतीय टीम के साथ तीन आईसीसी खिताब जीतने वाले कोचिंग दल का हिस्सा रहे। इनमें 2024 और 2026 के टी20 विश्व कप तथा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी शामिल हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कार्यकाल के दौरान भी वह टीम के साथ जुड़े रहे थे। अब वह मुंबई इंडियंस में रोहित के साथ फिर काम करेंगे। धवल कुलकर्णी भी मुंबई इंडियंस के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने आईपीएल के शुरुआती छह सत्रों में टीम का प्रतिनिधित्व किया और 2013 में उसकी पहली खिताबी जीत का हिस्सा बने। इसके बाद वह 2020 और 2021 में भी मुंबई

प्रीमियरलीग : माइकल ओवेन की भविष्यवाणी, चेल्सी से 3–1 से हारेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड

नई दिल्ली,एजेंसी। इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गज खिलाड़ी माइकल ओवेन ने प्रीमियर लीग में चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच होने वाले मुकाबले में चेल्सी की जीत की भविष्यवाणी की है। ओवेन के मुताबिक, मौजूदा परिस्थितियों में चेल्सी की टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को बोरनमाउथ ने हराया था। जियोस्टार को दिये एक साक्षात्कार में ओवेन ने कहा कि चेल्सी के प्रदर्शन में उतार–चढ़ाव जरूर रहा है, लेकिन टीम इस सत्र में शीर्ष चार के करीब है और उसके पास आक्रमण में कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं।

ओवेन ने चेल्सी के स्ट्राइकर जोआओ पेड्रो की तारीफ करते हुए उन्हें लंबे समय से कम आंका गया खिलाड़ी बताया। हालांकि, चोट के कारण वह इस मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे और उनकी जगह डैनी वेल्बेक को मौका मिल सकता है। ओवेन के अनुसार, मॉर्गन रोजर्स और कोल पापर की मौजूदगी में पेड्रो के बिना भी चेल्सी का आक्रमण काफी

13 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे। डफी ने 12वें ओवर में उन्हें आउट किया। डेरिल मिचेल और नाथन स्मिथ ने मिलकर बाउंड्री के पास उनका कैच पकड़ा। नमन के अलावा नितीश रेड्डी ने भी 10 गेंदों पर 2 छक्कों की बदौलत 21 रन बनाए। उन्हें सेंटरन ने अपना शिकार बनाया। तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में 35 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में चौके और छक्के लगाए और आखिरी तक संघर्ष जारी रखा। हालांकि, पारी के दूसरे अंतिम ओवर में मैथ्यू फिशर ने उनका विकेट लेकर भारत की बची हुई उम्मीदों को भी झटका दिया। प्रिंस यादव ने अंतिम ओवरों में कुछ तेज रन बनाए और 18 रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने चार ओवर में 23 रन देकर चार विकेट हासिल किए। मिचेल सैंटरन और मैथ्यू फिशर ने दो–दो, जबकि एडर्ड मिलने को एक सफलता मिली। इससे पहले ग्लेन फिलिप्स के शानदार शतक और माइकल ब्रेसवेल की तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को चौथे टी–20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत के खिलाफ सात विकेट पर 259 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

एक नजर

भूटान में ग्लेशियर झील फटने से बढ़ा बढ़ा का खतरा, कई नदी घाटियों में अलर्ट जारी



थिम्फू, एजेंसी । भूटान में ग्लेशियर झील फटने (जीएलओएफ) की घटना के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भूटान के राष्ट्रीय जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान केंद्र (एनसीएचएम) ने 29 अक्टूबर को सार्वजनिक परामर्श जारी कर संवेदनशील नदी घाटियों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अधिकारियों ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। एनसीएचएम के अनुसार, ग्लेशियर झील फटने के बाद ताक्त्सेमाखांग में सिंताफू, छू और लुंग्छू (गंगचेन टैंग छू) नदियों के संगम के पास एक कृत्रिम झील बन गई है। इस घटना के कारण नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। संभावित खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने मोछू और पुत्सांग्छू नदी घाटियों के आसपास रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। एनसीएचएम ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने, बाढ़ संभावित इलाकों में जाने से बचने और प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। केंद्र ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियर झील फटने के बाद नदी के प्रवाह में अचानक बदलाव आ सकता है, जिसका असर निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। एनसीएचएम ने बताया कि संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरे घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति का आकलन किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे स्थिति को लेकर नई जानकारी उपलब्ध होगी, आम लोगों को आगे के परामर्श और जरूरी अपडेट दिए जाएंगे। गौरतलब है कि, ग्लेशियर झील फटने की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक बाढ़ का कारण बन सकती हैं। ऐसे में भूटान के संवेदनशील नदी घाटियों में रहने वाले लोगों को प्रशासन की चेतावनी का पालन करने और पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

विवाह पंचमी से पहले जनकपुर-अयोध्या रेल सेवा के उद्घाटन की तैयारी तेज



काठमांडू। इस वर्ष विवाह पंचमी से पहले माता सीता की जन्मभूमि जनकपुरधाम और भगवान राम की नगरी अयोध्या और चारण से जोड़ने वाली विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारियाँ अंतिम चरण में पहुँच गयी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के प्रस्तावित भारत दौर के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से इस विशेष रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। नेपाल रेलवे कंपनी के प्रबंध निदेशक परिवेश पराजुली ने बताया कि हालाँकि, उद्घाटन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री शाह की भारत यात्रा के दौरान ही रेल सेवा शुरू करने की तैयारी का जवा है। प्रधानमंत्री शाह का 23 नवंबर को भारत दौरा प्रस्तावित है। पराजुली के मुताबिक रामायण सर्किट के तहत जनकपुरधाम से अयोध्या तक विशेष रेल सेवा संचालित करने के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा चल रही है। नेपाल की सीमा में ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेपाली सुरक्षा एजेंसियों तथा भारतीय क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जेम्हो है। इस व्यवस्था पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। कुछ दिन पहले नेपाल और भारत के रेलवे, सुरक्षा, सीमा शुल्क तथा आब्रजन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने विशेष निरीक्षण यात्रा से जयनगर-जनकपुरधाम-कुर्था रेलखंड का स्थलगत निरीक्षण भी किया था। जनकपुरधाम और अयोध्या के बीच सीधी रेल सेवा शुरू होने से दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिलने के साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जनकपुरधाम उड्डोग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ के मुताबिक माता सीता की जन्मभूमि जनकपुरधाम और भगवान राम की नगरी अयोध्या को सीधे रेल सेवा से जोड़ने के बाद रामायण सर्किट के तहत तीर्थयात्रियों और धार्मिक पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी। इस विशेष रेल सेवा से नेपाल और भारत के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियाँ भी बढ़ेंगी। फिलहाल भारत के जयनगर से नेपाल के जनकपुरधाम होते हुए पहाँचरी जिले के बिजलपुरा तक नियमित रेल सेवा संचालित हो रही है।

चक्रवात 'अर्णब' के असर से नेपाल में लगातार बारिश, जनजीवन प्रभावित

काठमांडू। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात 'अर्णव' के प्रभाव से गुरुवार रात से हो रही लगातार बारिश ने काठमांडू घाटी सहित नेपाल के कई हिस्सों में नज्जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बारिश के कारण सड़करी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूर भी प्रभावित हुए हैं। विभिन्न कामों से घरों से बाहर निकलने वाले लोग छूता और रैनकोट लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दिए। मौसम विज्ञानियों ने शुक्रवार को पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान बताया है। वहीं, कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। जल तथा मौसम विभाग की प्रवक्ता विष्णु पोखरेल ने बताया कि वैसे तो चक्रवात 'अर्णव' कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसके अवशेष प्रभाव से नेपाल में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं चल सकती हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विनोद पोखरेल ने बताया कि शुक्रवार दोपहर से रात तक कोशी और बागमती प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। चक्रवात का प्रभाव शनिवार से धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है।

नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा मजबूत करने पर सहमति, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल और भारत के बीच सीमा सुरक्षा, तकनीक आधारित प्रबंधन और द्विपक्षीय सहयोग के और मजबूत बनाने पर सहमति बनी है। काठमांडू में सशस्त्र बल नेपाल के महानिरीक्षक नारायणप्रताप पौडेल और भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के महानिरीक्षक संजय सिंहल के नेतृत्व में 28 – 29 अक्टूबर को यहां आयोजित नेपाल-भारत 10वीं समन्वय बैठक में यह सहमति बनी। बैठक में नौवीं समन्वय बैठक के फैसलों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही, सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों और सीमा पर अपराधों पर नियंत्रण के लिए रणनीतिक, परिचालन और कार्यक्षेत्र स्तर पर सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए दोनों देशों ने जल्द से जल्द सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

बैठक में दमगंजा (दोनों देशों की सीमा के बीच का जो मैसै लैंड) के प्रभावी प्रबंधन के लिए अनधिकृत खेती, अतिक्रमण और अवैध संरचनाओं को हटाने के संयुक्त प्रयास जारी रखने पर सहमति बनी। सीमा स्तंभों की मरम्मत, रखरखाव और पुनर्निर्माण के लिए संबंधित तंत्र के फैसलों के अनुसार जमीनी स्तर पर समन्वय बढ़ाने पर भी दोनों पक्ष सहमत हुए। इसी तरह, सीमा पर अपराधों के नेटवर्क, अवैध तस्करी, मानव तस्करी, नकली नोट और मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए सूचनाओं का नियमित आदान-प्रदान जारी रखने का निर्णय लिया गया। खुली सीमा का दुरुपयोग कर तीसरे देशों के नागरिकों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सीमा चौकियों पर जांच और दस्तावेजों के सत्यापन को



संरक्षित बनाने, दशगजा क्षेत्र में संयुक्त गश्त करने तथा संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में तत्काल सूचना साझा करने और भी सहमति बनी। सीमा प्रबंधन को आधुनिक और तकनीक अनुकूल बनाने के लिए दशगजा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रमुख सीमा चौकियों पर लॉज स्कैनर और वां-धू-मेटल डिटेक्टर लगाने तथा दोनों देशों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इससे अलावा, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और भ्रामक सूचनाओं से पैदा होते वाली सुरक्षा एवं सामाजिक सद्भाव संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। सीमा सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और विशेष प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के साथ ही दोनों सुरक्षा एजेंसियों के बीच नियमित अध्ययन दौरें आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए चिंतन का

कुनिटाट स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में संयुक्त जल बचाव अभ्यास (ज्वाइंट रिवफ्ट वाटर रेस्क्यू एक्सरसाइज) आयोजित करने के विषय पर भी चर्चा हुई। बैठक में वैद्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए सीमा चौकियों पर सहायता कक्षों का विस्तार करने पर सहमति बनी। इसके साथ ही खेलकूद, अंतरराष्ट्रीय दिवसों और प्रमुख त्योहारों के अवसर पर संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर आपसी विश्वास और सद्भाव बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में नेपाल की ओर से सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, नापी विभाग, नेपाल पुलिस और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं, भारत की ओर से सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारियों, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास तथा विदेश और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

बोस्निया में यूरोपीय संघ शांति मिशन के दौरान इटली का हेलीकॉप्टर क्रैश, चार सैन्यकर्मী शहीद

सारायेवो। बोस्निया में यूरोपीय संघ शांति मिशन के दौरान इटली का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चार सैन्यकर्मियों का

सर्वोच्च बलिदान हो गया। यूरोपीय संघ बल ने बताया कि गुरुवार शाम बोस्निया और हर्जोगोविना में नियमित प्रशिक्षण के दौरान यह चिनुक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चार सैन्य कर्मियों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए।

बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के बंजा लुका से प्रकाशित सर्बो-क्रोशियन भाषा के दैनिक समाचार पत्र 'ग्लास सर्पेक' की रिपोर्ट के अनुसार, यह हवाई हादसा ब्रको के पास गोरिस सेक्टर में हुआ। हादसे में वीरगति को प्राप्त होने वाले बहादुरों में दो इटली की आर्मा फोर्सेज और दो इटैलियन मिलिटरी रेडक्रॉस के सदस्य हैं। ११ घायलों में से दो की तुजला मैडिकल सेंटर रेफर किया गया है। नौ का ब्रको में इलाज चल रहा है। यूरोपीय संधि बल ने आधिकारिक बयान में कहा कि इस घटना में घायल सभी लोगों की हालत अभी स्थिर है। बल ने इस दुर्घटना से प्रकृतिको देखते हुए संधि से भ्रामक जानकारी फैलाने से बचने

की अपील की है। यूरोपीय संघ बल ने शहीद सैनिकों के परिवारों, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

यूरोपीय संघ बल के जनसंपर्क कार्यालय के बयान में कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की स्थानीय आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं और बल की संपर्क एवं निगरानी टीम के सदस्य तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ितों को बचने के चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया। इस घटना में कोई आम नागरिक घायल नहीं हुआ है और न ही नागरिकों के बुनियादी ढांचे, संपत्ति या वाहनों को कोई नुकसान पहुंचा है। इटली सरकार ने देश के चिह्नित सैन्य परिवारों में से पीड़ित परिवारों को उनके सदस्यों के नाम बता दिए हैं। इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी ने एकस पोस्ट में इस हादसे पर दुःख जताया है। उन्होंने पीड़ितों, उनके रिश्तेदारों और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए तैनात सभी कर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इटली सरकार की ओर से उपनाम सार्थक और एकजुटता भी जाहिर की।

नेपाल की 6 और चोटियों को 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वतों की सूची में शामिल कराने की पहल

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा (माउंट एवरेस्ट) के देश के रूप में जाना जाता है। नेपाल की आठ पर्वत चोटियों को पहले ही 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल चुकी है। अब नेपाल ने अपनी छह और चोटियों को इसी श्रेणी में शामिल कराने के लिए औपचारिक पहल की है।

काठमाडौं में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं पर्वतारोहण संघ (यूआईएएफ) की आमसभा के उद्घाटन सत्र में नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोहण समुदाय के सामने यह प्रस्ताव रखा। इस आमसभा में 45 देशों के 95 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल इससे पहले वर्ष 1982 और 2011 में भी यूआईएएफ की आमसभा की मेजबानी कर चुका है। नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) के अध्यक्ष फुर्बा ग्याल्जे शेर्पा ने आमसभा में इन छह चोटियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने एक अध्ययन रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें प्रत्येक चोटि को 8,000 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले स्वतंत्र पर्वत के रूप में मान्यता देने के आचार बताए गए हैं।

छह चोटियों की ऊँचाई

- * यालुंग कांग-8,505 मीटर
- * कंचनजंघा साउथ-8,476 मीटर
- * कंचनजंघा सेंट्रल-8,473 मीटर
- * ल्होत्से मिडिल-8,410 मीटर
- * ल्होत्से शार-8,400 मीटर
- * यालुंग कांग वेस्ट-8,077 मीटर

शेर्पा ने बताया कि एनएमए ने इन पर्वत



चोटियों की पहचान और ऊंचाई मापने पर एक अत्यन्त लक्ष्मण गणित किया था। अथर्व वेद प्रत्येक चोटी की कलाया भौगोलिक विज्ञान स्तंभ शिखर और अलग पर्वतारोहण माप प्रमाण जुटाए हैं। यदि इन सभी छह चोटी अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल जाती है, तो 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले माप पर्वतों की संख्या बढ़कर 14 और दुनिया पर्वतों की कुल संख्या 20 पहुंच जाएगी। समारोह को संबोधित करते हुए संस्कृत तथा नागरिक उड्डुन मंत्री खड्गाराज कहा कि दुनिया के 8,000 मीटर से अधिक वाले 20 पर्वतों में से 14 का नेपाल में है।

आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। मंत्री पौडेल के अनुसार इससे नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होंगी। साथ ही पर्वतारोहण, साहित्य पर्यटन, अनुसंधान, पर्वतीय अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के नए अवसर खुलेंगे। मंत्री पौडेल ने फेसबुक पर लिखा, "नेपाल का यह प्रस्ताव केवल पर्वतों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह तथ्यों, अध्ययन और वैज्ञानिक आधार के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने हमारी हिमालयी भौगोलिक पहचान, प्राकृतिक विरासत और पर्वतीय विशिष्टता स्थापित करने का प्रयास भी है।"

दीपावली से पहले नेपाल ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के सूखे मेवे आयात किए

काठमांडू, एजेंसी। दीपावली में अब महज एक सप्ताह से 10 दिन का समय बचा है। नेपाल के शहरों से लेकर गांवों तक त्योहार का माहौल बनने लगा है। रंग-बिरंगी रोशनी, गेंदे और सयपत्री के फूलों की खुशबू के बीच तिरहा की एक खास परंपरा भाई मसाला की खरीदारी भी शुरू हो गई है। भाई टीका के दिन बहनें अपने भाइयों को सूखे मेवे और मेवों से भरे पैकेट भेंट करती हैं। हालांकि, इस परंपरा को निभाने के लिए नेपाल की निर्भता विदेशी बाजारों पर काफी अधिक है। सीमा शुल्क विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिवाली, भैयादूज और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए नेपाल ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के सूखे मेवे आयात किए हैं। अखोट, काजू और बादाम का आयात ही पहली तिमाही में 150 करोड़ रुपये से अधिक का रहा। इसमें सुपारी, नारियल, अंजीर, किशमिश और भुने हुए मेवों को शामिल करने पर कुल आयात का मूल्य 300 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच जाता है। आंकड़ों के अनुसार दिवाली से ठीक पहले आने वाले महीने में व्यापारियों ने पिछले दो महीनों की तुलना में काफी अधिक मात्रा में सूखे मेवे आयात किए। इससे त्योहार के दौरान उपहार और घरेलू खपत के लिए बढ़ने वाली मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है।

नेपाल को चीन और चिली से मिलता है अखरोट छिलके सहित अखरोट के आयात का कारोबार में बड़ा हिस्सा है। पिछले एक महीने में नेपाल ने 14 लाख अखरोट किलोग्राम छिलके वाले अखरोट आयात किए। इसके लिए 57 करोड़ 33 लाख 70 हजार रुपये का भुगतान किया गया। सरकार को इस आयात से 13 करोड़ 93 लाख 68 हजार रुपये राजस्व प्राप्त हुआ। नेपाल में अखरोट का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता चीन है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आयात किए गए छिलके वाले अखरोट में से 12 लाख 88 हजार किलोग्राम चीन से आया थे। दक्षिण अमेरिकी देश चिली दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। उसने नेपाल को 1 लाख 51 हजार 225



किलोग्राम अखरोट निर्यात किए थे। अन्य देशों में भारत से 901 किलोग्राम, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 47 किलोग्राम, कतर से 26 किलोग्राम, सऊदी अरब से 5 किलोग्राम और मलेशिया से 2 किलोग्राम अखरोट आयात किए गए। बिना छिलके वाले अखरोट का आयात भी बढ़ा है। गत एक महीने में नेपाल ने 74 हजार 51 किलोग्राम अखरोट आयात किए, जिनका मूल्य 8 करोड़ 6 लाख रुपये से अधिक था। पिछले वर्ष की समान अवधि में लगभग 18 हजार किलोग्राम अखरोट आयात किए गए थे और ये सभी चीन से आए थे।

अमेरिकी बादाम नेपाली घरों तक पहुंच रहे
 बादाम भी नेपाल के त्योहार बाजार में अधिक कीमत वाले प्रमुख सूखे मेवों में शामिल हैं। त्योहार को लक्षित करते हुए पिछले एक महीने में नेपाल ने 50 लाख 60 हजार 79 किलोग्राम बिना छिलके वाले बादाम आयात किए, जिनका मूल्य 47 करोड़ 68 लाख 10 हजार रुपये

था। पिछले जित्त वर्ष की समान अवधि में 4 लाख 2 हजार 368 किलोग्राम बादाम आयात किए गए थे। नेपाल की बादाम की सबसे अधिक आपूर्ति अमेरिका से होती है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार, आयात किए गए लगभग 4 लाख किलोग्राम बादाम में से 3 लाख 98 हजार 212 किलोग्राम अमेरिका से आए थे। भारत 2,625 किलोग्राम बादाम के साथ दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था। इसके अलावा सऊदी अरब से 598 किलोग्राम, कुवैत से 479 किलोग्राम, कतर से 272 किलोग्राम, यूएई से 130 किलोग्राम, बहरीन से 29 किलोग्राम, चीन से 11 किलोग्राम और ओमान से 1 किलोग्राम बादाम आयात किए गए थे।

काजू की आपूर्ति में वियतनाम और भारत अग्रणी हैं। नेपाल ने पिछले महीने 4 लाख 69 हजार 416 किलोग्राम बिना छिलके वाले काजू आयात किए। इससे कुल मूल्य बढ़ कर 56 लाख 78 हजार रुपये था। वियतनाम नेपाल को काजू का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। उसने 2 लाख 8 हजार 674 किलोग्राम काजू निर्यात किए हैं। भारत 1 लाख 56 हजार 21 किलोग्राम के काजू दूसरे स्थान पर था। पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट 30 हजार किलोग्राम काजू के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीन से 9,089 किलोग्राम और वेनेजुएला से 5,148 किलोग्राम काजू आयात किए गए थे। इसके अलावा खाड़ी देशों से भी काजू की आपूर्ति हुई। कतर से 509 किलोग्राम, यूएई से 199 किलोग्राम, कुवैत से 124 किलोग्राम, सऊदी अरब से 93 किलोग्राम और बहरीन से 24 किलोग्राम काजू आयात किए गए।

भुने और नमकीन मेवों की बढ़ रही मांग
नेपाल में कच्चे मेवों की तुलना में भुने और नमकीन काजू तथा पिस्ता की मांग बढ़ रही है। पैकेटों में बिकने वाले ये तैयार उत्पाद आमतौर पर अधिक कीमत पर उपलब्ध होते हैं। वियतनाम से हुए काजू का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। उसने 19 हजार किलोग्राम काजू निर्यात किए। अजितका मूल्य 2 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक

था। भारत ने 14 हजार 919 किलोग्राम, चीन ने 11 हजार 600 किलोग्राम, यूएन ने 6 हजार 237 किलोग्राम और थाईलैंड ने 372 किलोग्राम भुने हुए काजू नेपाल भेजे हैं। भुने और नमकीन पिस्ता के बाजार में चीन का दबदबा है। नेपाल ने चीन से 87 हजार 658 किलोग्राम पिस्ता आयात किए, जिनका मूल्य 11 करोड़ 56 लाख रुपए था। इंडोनेशिया से 11 हजार 201 किलोग्राम, अमेरिकी से 7,938 किलोग्राम, भारत से 2,265 किलोग्राम और थाईलैंड से 227 किलोग्राम पिस्ता आयात किए गए। इसके मुकाबले बिना छिलके वाले कच्चे पिस्ता का आयात काफी कम रहा। नेपाल ने एक महीने में ही 1,936 किलोग्राम कच्चे पिस्ता आयात किए। इसके अलावा भारत से 316 किलोग्राम और थाईलैंड से 120 किलोग्राम भुने हुए बादाम भी आयात किए गए।

सुपारी, नारियल और अंजीर से भी बड़ रह आयत बिल

अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता के अलावा नेपाल त्योहारों में उपहार के रूप में दिए जाने वाले अन्य सूखे मेवों का भी बड़े पैमाने पर आयात करता है। पिछले एक महीनों में नेपाल ने 32 लाख 40 हजार किलोग्राम सुपारी आयात की, जिसका मूल्य 84 करोड़ 77 लाख रुपये था। इसी अवधि में 8 लाख 36 हजार किलोग्राम सूखा नारियल आयात किया गया, जिसकी कीमत 2 करोड़ 59 लाख रुपये थी। इसके अलावा देश ने 1,41,2 किलोग्राम सूखी खजूर और 678 किलोग्राम ताजी खजूर आयात की। अंजीर का आयात 45 हजार किलोग्राम से अधिक रहा। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद नेपाल त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले कई सूखे मेवों के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर है। देश के कुछ हिस्सों में अखरोट और बादाम की व्यावसायिक खेती के लिए अनुकूल जलवायु होने की संभावना के बावजूद इनका घरेलू उत्पादन सीमित है। इसी वजह से त्योहारों के समय मांग बढ़ने पर नेपाल को बड़ी मात्रा में सूखे मेवे विदेश से आयात करने पड़ते हैं।

एक नजर

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, महिला सहित तीन को 10-10 वर्ष का कारावास

फ़िरोजाबाद,एजेंसी। न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास व तीन अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर अर्धदंड भी लगाया है। अर्धदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला दक्षिण थाना क्षेत्र से जुड़ा है। थाना क्षेत्र अन्तर्गत रहने वाला एक नाबालिग 30 मार्च 2023 की शाम माता रानी के नेजा के साथ गई थी। जिसके बाद वापस नहीं लौटी। मां ने थाने पर पुत्री की गुमशुदी दर्ज कराई। पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया। जांच के बाद अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र सरजू प्रसाद निवासी जसवंत नगर इटावा, विशाल उर्फ बासुदेव पुत्र राम सिंह, दीसी पत्नी विशाल, कुलदीप पुत्र दौलतराम निवासीगण अशर्णी नगर हिमायूंपुर के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने जांचोपरांत इन सभी के विरुद्ध नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म और साजिश रचने की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश प्रधान न्यायालय पोक्सो मुमताज अली के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किये गए। विद्वान न्यायाधीश मुमताज अली ने पत्रावली पर मौजूद गवाहों की गवाही व साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दिनेश कुमार को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा व 55,000 रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया है। अर्धदण्ड न देने पर 18 माह, 07 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी होगी। वहीं न्यायालय ने इस मामले में सह अभियुक्त विशाल उर्फ बासुदेव, दीसी व कुलदीप को दोषी पाते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास 23-23 हजार रुपए के अर्धदंड से दंडित किया है। अर्धदंड अदा न करने पर तीनों दोषियों को 11-11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा।

गाजियाबाद डीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हाईकोर्ट, नये सिर से मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज,एजेंसी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा दाखिल हलफनामे और उसके साथ लगाई गई जांच रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने बिजेंद्र कुमार की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में शिकायत को दबाने का स्पष्ट प्रयास दिखाई देता है। आईएसएस गाजियाबाद के जिलाधिकारी रवींद्र कुमार मंदार ने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया कि फरवरी 2026 में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी। समिति ने 17 फरवरी 2026 को डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। कोर्ट ने पाया कि हलफनामे के साथ संलग्न रिपोर्ट पर समिति के अन्य दो सदस्यों, यानी क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, गाजियाबाद और थानाध्यक्ष, मुरादनगर के हस्ताक्षर नहीं थे।

अदालत में उपस्थित डीएम ने कहा कि यह रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष द्वारा दी गई है और अध्यक्ष के हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट को समिति की रिपोर्ट माना जाना चाहिए। हलफनामे में कहा गया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद मामला 25 फरवरी 2026 को ‘आवश्यक कार्रवाई’ के लिए क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को भेज दिया गया। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब वह अधिकारी स्वयं समिति के आवश्यक सदस्य हैं और उन्हें रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने थे, तो रिपोर्ट उन्हीं के पास कार्रवाई के लिए क्यों भेजी गई। कोर्ट ने कहा, ‘हम डीएम के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं’ और टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की शिकायत में उठाए गए मुद्दों को दबाने का स्पष्ट मामला प्रतीत होता है। राज्य की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि डीएम अपने इन हलफनामे को लेकर खेद व्यक्त कर रहे हैं और अगली तारीख पर नया हलफनामा दाखिल करेंगे। कोर्ट ने कहा समिति शिकायत की गहनता से जांच कर, शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य एकत्र कर और उनका मूल्यांकन कर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश की जाए।जिलाधिकारी, गाजियाबाद अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें। अगली सुनवाई 19 नवंबर 2026 को होगी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के कर्मचारियों ने 20 साल पुराने गतिरोध को ऐतिहासिक और सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रशासन की सराहना की

एम.जबिउल्लाह, सद्भावना टुडे नई दिल्ली। आज दोपहर 3:30 बजे अंसारी ऑडिटोरियम के लॉन में आयोजित एक धन्यवाद कार्यक्रम में, जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) के 2,000 से अधिक टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान, विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों ने छात्र संघ चुनावों के मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए जेएमआई प्रशासन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों के हितों की रक्षा करने और शिक्षण तथा प्रतीक्षा प्रक्रियाओं को हर हाल में निर्बाध बनाए रखने के लिए प्रशासन की स्पष्टवादिता और सुझबूझ की सराहना की। उन्होंने कल, 29 अक्टूबर, 2026 को जारी किए गए महत्वपूर्ण आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रशासन के "अत्यधिक धैर्य, विवेक और समझदारी" को दर्शाता है। साथ ही, यह जेएमआई के 106वें स्थापना दिवस पर संस्थान की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन के अनुकरणीय प्रयासों की भी प्रमाण है।

जेएमआई कर्मचारियों ने पिछले दो सप्ताह में भारत सरकार, विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए भी अपना आभार व्यक्त किया। यह ध्यान दिया गया कि छात्र संघ चुनावों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को बातचीत और विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाने के लिए जेएमआई प्रशासन की प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ यह लगभग आठवीं

जमीअत उलमा की प्रबंध समिति के सम्मेलन में मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाने की कठोर निंदा

नई दिल्ली/मेवात। जमीअत उलमा-ए-हिंद की प्रबंध समिति का वार्षिक सम्मेलन शुक्रवार को हरियाणा के मेवात जिला के नूंह में पीपाका सहस्रौला पट्टी स्थित डीएलएफ स्प्रिंगफील्डमें जमीअत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी द्वारा ध्वजारोहण के साथ आरंभ हुआ। सम्मेलन में देशभर से लगभग दो हजार सदस्य, प्रमुख हस्तियां और प्रसिद्ध उलमा भाग ले रहे हैं। इसके प्रारंभिक सत्र में इस्लामी मंदरसों के संरक्षण, देशभर में मस्जिदों, ईदगाहों और अन्य इस्लामी धार्मिक स्थलों के विरुद्ध की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयों पर रोक तथा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इस अवसर पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में मुसलमानों के वर्तमान हालात पर भी प्रकाश डाला। उनका विस्तृत संबोधन बाद में होगा। इस अवसर पर पारित किए गए प्रस्तावों में मंदरसों को मान्यता और जांच के नाम पर परेशान करने, उनके विरुद्ध निराधार प्रचार करने तथा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को विवादों में घसीटने की कोशिशों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। भारत सरकार और संबंधित कानूनी संस्थाओं से मांग की गई कि ऐसी कार्रवाइयों को तत्काल बंद किया जाए और भारतीय संविधान के अंतर्गत मंदरसों को प्राप्त अधिकारों एवं संरक्षण की गारंटी सुनिश्चित की जाए।

सम्मेलन में मंदरसों के जिम्मेदारों को भी ध्यान दिलाया गया कि वह अपने संस्थानों की



भूमि संबंधी दस्तावेज, स्वीकृत नक्शे, छात्रवासों में रहने वाले विद्यार्थियों के पहचान संबंधी विवरण तथा वित्तीय खातों का ऑडिट पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार करके सुरक्षित रखें। मस्जिदों और अन्य इस्लामी धार्मिक स्थलों के संरक्षण से संबंधित दूसरे प्रस्ताव में देशभर में मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों और अन्य धार्मिक स्थलों की निशाना बनाए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया कि मस्जिदें केवल इमारतें नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों की आस्था, सामूहिक पहचान और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 एवं 26 के अंतर्गत प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता की व्यावहारिक अभिव्यक्ति हैं। प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविज़न्स) एक्ट, 1991 के महत्व पर जोर देते हुए कहा गया कि इस कानून

का मूल उद्देश्य धार्मिक स्थलों की धार्मिक स्थिति को यथावत बनाए रखना और ऐतिहासिक विवादों को दोबारा खोलने से रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या फैसले में भी इस कानून को संविधान के मूल धर्मनिरपेक्ष ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अधीनस्थ अदालतों द्वारा इस कानून की भावना की अनदेखी करते हुए धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण के आदेश जारी किए जाने पर चिंता व्यक्त की गई। इस संबंध में संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद का उल्लेख करते हुए कहा गया कि एकतरफा सर्वेक्षण के आदेश के बाद पैदा हुई स्थिति ने शांति और कानून-व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। प्रबंध समिति ने भारत सरकार और उच्च न्यायपालिका से मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 के अंतरिम

आदेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए तथा 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के विपरीत नए दावों को प्रारंभिक चरण में ही खारिज किया जाए। इसी प्रकार नगरपालिका, राजस्व और विकास प्रधिकरणों द्वारा उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना तथा प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का न्यायसंगत अवसर दिए बिना मस्जिदों को ध्वस्त करने की कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए। कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि जमीअत उलमा-ए-हिंद की सभी राज्य, जिला और तहसील स्तर की इकाइयां केंद्रीय जमीअत द्वारा निर्धारित एक ही तारीख और समय पर अपने-अपने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन

मूल्य संवर्धन और आधुनिक तकनीक से बढ़ेगी देश के मछुआरों की आय

नई दिल्ली। मूल्य संवर्धन और आधुनिक तकनीक से न केवल देश के मछुआरों की आय बढ़ेगी अपितु उत्पादन से बाजार तक बदलेगा और मत्स्य क्षेत्र का स्वरूप भी बदलेगा। यानी भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र अब पारंपरिक मछली उत्पादन की सीमाओं से आगे बढ़कर बाजारोंन्मुख उद्यमिता के नए दौर में प्रवेश कर रहा है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने, मछुआरों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने तथा समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं, बुनियादी ढांचे में निवेश और तकनीकी नवाचारों के परिणामस्वरूप मत्स्य क्षेत्र की पूरी मूल्य शृंखला में बदलाव देखने को मिल रहा है। मत्स्य विभाग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि मछली उत्पादन के साथ-साथ अब उसके प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, भंडारण और विपणन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट मत्स्य उत्पादों की बढ़ती मांग ने मूल्य संवर्धन आधारित कारोबार के लिए नए अवसर खोले हैं। इससे उत्पादकों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता, भंडारण अवधि और बाजार तक पहुंच में सुधार होने से फसलोत्तर नुकसान को कम करने में भी मदद मिल रही है। मत्स्य क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 से सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है। नीली

भारत, बेल्लिजयम और लक्जमबर्ग एयरोस्पेस, रिसर्च तथा इनोवेशन में बढ़ाएंगे सहयोग

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत, बेल्लिजयम और लक्जमबर्ग ने अपने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश साझेदारियों की समीक्षा की है। इसके साथ ही एयरोस्पेस, अनुसंधान, नवाचार और उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर अपनी सहमति जताई है। भारत-बेल्लिजयम-लक्जमबर्ग आर्थिक संघ (बीएलईयू) के संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 19वां सत्र 29 अक्टूबर को लक्जमबर्ग में आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत, बेल्लिजयम और लक्जमबर्ग ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों की समीक्षा के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ करने के अवसरों पर विचार-विमर्श किया। संयुक्त आर्थिक आयोग की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल, बेल्लिजयम के संघीय लोक सेवा विदेश मामले, विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग विभाग के भू-अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक कूटनीति महानिदेशक फिलिप वांडेन बुल्के तथा लक्जमबर्ग के विदेश एवं यूरोपीय मामलों, रक्षा, विकास सहयोग एवं विदेश व्यापार मंत्रालय के महासचिव हेनरी शुमाकर ने की।

वाणिज्य मंत्रालय के मुनाबिक 19वें सत्र में भारत, बेल्लिजयम और लक्जमबर्ग के बीच वर्तमान व्यापार एवं निवेश संबंधों की समीक्षा की गई। साथ ही, आर्थिक सहभागिता बढ़ाने, व्यापार एवं निवेश प्रवाह को सुगम बनाने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में विमानन एवं अंतरिक्ष क्षेत्र, अनुसंधान एवं नवाचार, उच्च शिक्षा तथा कोशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति बनी। व्यापार संबंधी चिंताओं का समाधान करने, बाजार



तक पहुंच सुगम बनाने तथा आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के अवसरों की पहचान करने के उद्देश्य से बाजार संबंधी मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। मंत्रालय ने कहा कि संयुक्त आर्थिक आयोग की इस बैठक में तीनों पक्षों को अपनी आर्थिक प्रार्थमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करने तथा कारोबारी सहभागिता एवं निवेश साझेदारियों को बढ़ावा देने के नए अवसरों की पहचान करने का अवसर मिला। वहीं, चर्चा के दौरान भारत, बेल्लिजयम और लक्जमबर्ग के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में निरंतर संवाद एवं सहयोग के महत्व की पुनः पुष्टि की गई। इसके अलावा संयुक्त आर्थिक आयोग के सत्र के बाद वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने लक्जमबर्ग स्थित कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ व्यावसायिक बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक विकास दर और निवेश

की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने वित्तीय सेवाओं, उन्नत विनिर्माण, रसद, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा तथा अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का भी उल्लेख किया।

उन्होंने लक्जमबर्ग की कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ एकीकरण के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक में कई प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई। इन्में रसद, विशेष रूप से हवाई संपर्क एवं बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं एवं फिनटेक, डिजिटल परिवर्तन एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), स्वास्थ्य सेवा एवं जीवन विज्ञान, आयुर्वेद एवं पारंपरिक चिकित्सा तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल थे।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज वित्तीय घोटाला : पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बाद अब सुमन हाजरा को मिली सशर्त जमानत

कोलकाता। आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए करोड़ों रुपये के वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में एक और आरोपित को जमानत मिल गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ‘हाजरा मेडिकल’ के मालिक सुमन हाजरा को सशर्त जमानत दे दी। यह फैसला न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की एकल पीठ ने सुनाया। इससे पहले इसी मामले में मुख्य आरोपित और आर.जी. कर के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को भी जमानत मिल चुकी है। सुमन हाजरा पर आरोप था कि उन्होंने डॉ. संदीप घोष के साथ साठगांठ कर चिकित्सा उपकरण खरीद में भ्रष्टाचार किया था। इसी आरोप के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें दो सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने हाजरा की जमानत के लिए कुछ कड़ी शर्तें भी तय की हैं।

अदालत के निर्देशानुसार, सुमन हाजरा को निचली अदालत में 20 हजार रुपये के दो जमानती बांड जमा करने होंगे। जमानत पर रिहा होने के बाद, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत की सभी सुनवाईयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। अदालत ने हाजरा के कोलकाता, हावड़ा और विधाननगर



(साल्टलेक) इलाकों से बाहर जाने पर भी सख्त रोक लगा दी है। इसके अलावा, उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और सीबीआई के जांच अधिकारी को अपना एक विशेष मोबाइल नंबर भी देना होगा, जिसे बदला नहीं जा सकेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि हाजरा किसी भी सूरत में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सीबीआई के अनुसार, सुमन हाजरा आर.जी. कर अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के व्यवसाय से जुड़े थे। जांचकर्ताओं का आरोप है कि हाजरा ने पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के करीबी सहयोगी के रूप में अस्पताल की खरीद और टेंडर (निविदा) प्रक्रिया में अवैध तरीके से अपना प्रभाव डाला। आरोप है कि 2021 से 2024 के बीच

अस्पताल में चिकित्सा उपकरण और दवा खरीद में धांधली करने के लिए एक ‘कॉर्टेल’ (गिरोह) बनाया गया था, जिसके केंद्र में डॉ. संदीप घोष थे। इस कॉर्टेल के प्रमुख सदस्यों के रूप में सुमन हाजरा और एक अन्य व्यवसायी बिप्लव सिंहा का नाम सामने आया था। आरोप है कि इन लोगों ने अन्य व्यापारियों को टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने से रोका और अपनी पसंदीदा कंपनियों को ही टेंडर दिलाने की व्यवस्था की। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया को दारुिकार करने और बाजार दर से अधिक कीमत पर चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी) , से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से

प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)

